आज का विचार

इंसान तब सफल नहीं होता जब वह दुनिया को बदलता है, बल्कि तब सफल होता है जब वह खुद को बदलना शुरू कर देता है।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

7

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़। शनिवार, 21 फरवरी, 2026 | वर्ष 24, अंक 44, मूल्य: 3 रुपए, | पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 | www.citydarpan.com

पीएम ने एआई और गहन तकनीक स्टार्टअप्स के सीईओ से की बातचीत, नवाचार और अनुसंधान पर दिया बल

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के अंतिम दिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और गहन तकनीक क्षेत्र से जुड़े प्रमुख स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हेल्थकेयर, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और अन्य उभरते क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय स्टार्टअप्स की तकनीकी परियोजनाओं और नवाचारों की जानकारी ली।

प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान स्टार्टअप्स के सीईओ के साथ गहन चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न तकनीकी समाधानों, अनुसंधान और उत्पाद विकास से जुड़े पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की। स्टार्टअप्स ने अपने एआई आधारित समाधान और उनके सामाजिक तथा आर्थिक

प्रभाव के बारे में जानकारी दी।

बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता , मशीन लर्निंग और गहन तकनीक तकनीक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती हैं। प्रधानमंत्री ने नवाचार, अनुसंधान और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप तकनीक विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के युवा और उद्यमी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं और देश को तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सरकार का फोकस तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और डिजिटल समाधान विकसित करने पर है।

नई दिल्ली में आयोजित पांच दिवसीय एआई इम्पैक्ट समिट का शुक्रवार को समापन हो रहा है। 16 फरवरी से शुरू हुए इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और डारियो अमोदेई सहित कई वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रमुखों ने एआई के भविष्य, उसके उपयोग और उससे जुड़ी चुनौतियों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने भी विभिन्न सत्रों में भाग लेकर भारत की तकनीकी क्षमता और एआई के क्षेत्र में देश की भूमिका को रेखांकित किया।

एआई गवर्नेंस प्रगति पर ब्रेक नहीं, बल्कि समाधान का एक्सीलरेटर है : यूएन महासचिव

दिल्ली स्थित भारत मण्डपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन में शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि विज्ञान आधारित एआई गवर्नेंस प्रगति पर ब्रेक नहीं, बल्कि समाधान का एक्सीलरेटर है। उन्होंने आगाह किया कि यदि एआई के लिए साझा वैश्विक मानक नहीं बने, तो दुनिया भर में नियमों का ह्लपैचवर्कह्व तैयार हो जाएगा, जिससे लागत बढ़ेगी, सुरक्षा कमजोर होगी और असमानताएं गहरी होंगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि स्पष्ट और भरोसा पैदा करने वाले नियम व्यवसायों को दिशा देते हैं, जिससे नवाचार सही रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। विज्ञान आधारित शासन प्रगति को रोकता नहीं है, बल्कि उसे अधिक सुरक्षित, निष्पक्ष और व्यापक रूप से साझा करने योग्य बनाता है। एंटोनियो गुटेरेस जोर देकर कहा कि एआई के प्रभाव बच्चों की सुरक्षा, श्रम बाजार में बदलाव और बड़े पैमाने पर हेरफेर जैसे जोखिम का समय रहते आकलन जरूरी है, ताकि देश अपने नागरिकों को तैयार कर सकें, उनकी रक्षा कर सकें और उनमें निवेश कर सकें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह भी कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय सहयोग चुनौतीपूर्ण है, विश्वास कमजोर हुआ है और तकनीकी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। अलग-अलग देशों और क्षेत्रों में असंगत नीतियां और तकनीकी मानक लागू हैं। नियमों में इस तरह की असमानता से लागत बढ़ेगी, सुरक्षा कमजोर होगी और वैश्विक विभाजन गहरा होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि साझा बेंचमार्क तय हों, तो दिल्ली का कोई स्टार्टअप भी वैश्विक स्तर पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है और सुरक्षा मानक तकनीक के साथ-साथ आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञान मार्गदर्शन देता है, लेकिन निर्णय इंसान लेते हैं। उन्होंने उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों न्याय, स्वास्थ्य सेवाएं और ऋण में सार्थक मानवीय निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। लोगों को यह समझने और चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए कि निर्णय कैसे लिए गए।

मोदी-गुटेरेस ने एआई को समावेशी बनाने में यूएन की भूमिका पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को समावेशी बनाने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट में बताया कि इस बैठक में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को लेकर चर्चा की, जिनका उद्देश्य एआई को सभी के लिए लाभकारी और सुलभ बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारत की मानवकेंद्रित एआई विकास पहल का उल्लेख किया, जिसमें ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सुधार आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा कि एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैठक में हमने चर्चा की कि एआई को सर्वसमावेशी कैसे बनाया जाए और इसमें संयुक्त राष्ट्र की रचनात्मक भूमिका क्या हो सकती है। भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जिनका उद्देश्य एआई का उपयोग बेहतर ग्रह के लिए करना है। बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर भी विचार-विमर्श हुआ, खासकर ग्लोबल साउथ को अधिक आवाज देने के मुद्दे पर।

मुख्यमंत्री सैनी ने पेश किया सरकारी संकल्प, विधानसभा में हुआ पारित

हरियाणा आवासन बोर्ड का एचएसवीपी में हुआ विलय

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, नागरिकों को बेहतर आवासन सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा शहरी योजना एकीकरण में सुधार के उद्देश्य से आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन हरियाणा विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश करते हुए बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आवासन बोर्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, दोनों के कार्य लगभग एक समान थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि आवासन बोर्ड हरियाणा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है।

यह संकल्प हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 80 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। अब बोर्ड की सभी जिम्मेदारियां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की होंगी।

बजट सत्र के प्रथम दिन महान विभूतियों एवं वीर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के प्रथम दिन सदन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान विभूतियों, उनके सगे-संबंधियों तथा वीर सैनिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की। विपक्ष सहित सभी सदस्यों ने शोक प्रस्ताव का समर्थन किया। सदन में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, भूतपूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र कुमार मदान, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य आनंद कौशिक के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने भी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आदित्य चौटाला ने भी अपनी पार्टी की ओर से दिवंगतों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सदन में प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अश्रुपूर्ण नमन किया गया, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों में सूबेदार हीरा लाल (गांव अकबरपुर, जिला महेंद्रगढ़), सूबेदार धर्मवीर (गांव बिरोहड़, जिला झज्जर), उप-निरीक्षक आकाश चौधरी (गांव रूदड़ौल, जिला चरखी दादरी), हवलदार हरजिंदर सिंह (गांव मंगोली रांगड़ान, जिला कुरुक्षेत्र), हवलदार जोगेंद्र सिंह (गांव बड़कोदा, जिला महेंद्रगढ़), नायक प्रवीण कुमार (गांव शेरिया, जिला झज्जर), नायक दीपक गोयत (गांव कापड़ो, जिला हांसी), सिपाही सुधीर नरवाल (गांव शेरपुर, जिला यमुनानगर), सिपाही जोगेंद्र (गांव मय्यड़, जिला हिसार), सिपाही मोहित (गांव गिजाड़ौद, जिला झज्जर), सिपाही साहिल मीणा (गांव जडथल, जिला रेवाड़ी), सिपाही मनीष कुमार (गांव सुलेहड़ा, जिला जींद) तथा सिपाही सुरजीत (गांव ढुकड़ा, जिला सिरसा) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विधायक मामन खान के भतीजे साहिल खान, विधायक राम करण के भाई केसर सिंह तथा विधायक सरदार मनदीप चट्ठा की माता श्रीमती निर्मल दीप चट्ठा के निधन पर भी सदन ने गहरा शोक प्रकट किया। सदन में सभी दिवंगत आत्माओं की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मान सरकार का गैंगस्टरों पर वार जारी एक माह में 10 हजार से अधिक गिरफ्तार

- मान के नेतृत्व में 'गैंगस्टरां ते वार' गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक जंग

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेशों पर शुरू की गई मुहिम 'गैंगस्टरां ते वार' के एक महीना पूरा होने पर पंजाब पुलिस ने मुहिम की शुरूआत से अब तक पूरे राज्य में 32,342 छापेमारी करके गैंगस्टरों और उनसे जुड़े अपराधियों समेत 10,412 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

उल्लेखनीय है कि, जो 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। सभी जिलों की पुलिस टीमें गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े पहचाने गए और मैप किए गए स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं।

विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि पुलिस टीमों ने गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से 205 हथियारों सहित 396 जिंदा कारतूस और 34 मैगजीन, 104 तेजधार हथियार और चार हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं।इसके अलावा, 5,294 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई है, जबकि 10,090 व्यक्तियों की जांच की गई और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि मुहिम शुरू होने से अब तक पुलिस टीमों ने 664 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

उल्लेखनीय है कि 31वें दिन पुलिस टीमों ने 664 ठिकानों पर छापेमारी करके 198 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जबकि 100 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई और 18 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने कहा कि लोग गुप्त रूप से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर-93946-93946 के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना/जानकारी भी साझा की जा सकती है।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' के 356वें दिन भी जारी रखी है, जिसमें 87 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 458 ग्राम हेरोइन, 600 ग्राम अफीम, 439 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 2200 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है। इसके साथ ही केवल 356 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 50,496 हो गई है। नशा छुड़ाने की मुहिम के तहत पंजाब पुलिस ने आज 26 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है।

भारत 'पैक्स सिलिका' रणनीतिक गठबंधन में शामिल

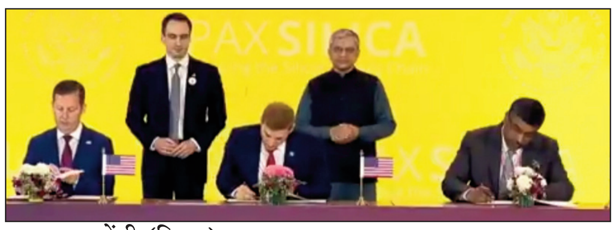

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया है। समझौता महत्वपूर्ण खनिजों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला बनाने से जुड़ा है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान इस पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करना है।

भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में एक समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग की उपस्थिति में इसपर हस्ताक्षर किए गए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने कहा कि पैक्स सिलिका इस बात की घोषणा है कि भविष्य उनका है जो निर्माण करते हैं और जब स्वतंत्र समाज साथ आते हैं तो नई संभावनाएं बनती हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैक्स सिलिका समझौता सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, विनिर्माण और चिप डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे देश में संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर नाथुनपुर में अमित शाह ने 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II' का किया शुभारंभ

एजेंसी (हि.स.)

कछार (असम)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कछार जिले के भारत-बांग्लादेश सीमा स्थित नाथुनपुर में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-क्क' का शुभारंभ किया। इस अवसर को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव अब देश के विकास के नए केंद्र बनेंगे। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती गांवों को 'राष्ट्र के प्रथम गांव' की नई पहचान देने की बात कही।

केंद्रीय गृहमंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगाए गए 20 स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल का भी अवलोकन किया और महिला उद्यमियों से संवाद किया। इन स्टॉलों में

स्थानीय हस्तशिल्प, वस्त्र और अन्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल बराक घाटी की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की बढ़ती भावना को दर्शाती है और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II' के तहत असम के 9 जिलों के 140 गांवों, जिनमें कछार जिले के 11 गांव शामिल हैं, का समग्र विकास किया जाएगा। इन गांवों में विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना, बेहतर सड़क संपर्क और सतत आजीविका के अवसर विकसित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति, सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था और मजबूत दूरसंचार नेटवर्क सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों का आर्थिक सशक्तिकरण हो और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में असम उपेक्षा से सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हुआ है और सीमावर्ती क्षेत्र अब 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप विकास के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री का बराक घाटी की पारंपरिक अस्मिता के प्रतीकों - उत्तरिया, रोंगमेई नगा हस्तबुनी शॉल तथा पारंपरिक मैतेई चटाई से स्वागत किया, जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दशार्ता है।

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता अप्रैल में लागू होने की संभावना: गोयल

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होने और अप्रैल में इसके लागू होने की संभावना जताई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि भारत के ब्रिटेन और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अप्रैल में लागू होने की उम्मीद है। पीयूष गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ समझौता सितंबर में लागू हो सकता है। भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि ईयू के सभी 27 देश इस बात के लिए उत्सुक हैं कि एफटीए को जल्द ही फाइनल किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। गोयल ने कहा कि यह समझौते 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है।

भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए तीन दिवसीय बैठक 23 फरवरी से अमेरिका में शुरू होगी। इस महीने की शुरूआत में भारत-अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में घोषणा की थी कि अंतरिम व्यापार समझौते के लिए रूपरेखा तय कर ली गई है।

शिक्षामित्रों को 18 हजार तो अनुदेशकों को मिलेगा 17 हजार रुपये मानदेय

सिटी दर्पण संवाददाता

लखनऊ

- मुख्यमंत्री योगी ने सदन में गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में अपनी सरकार की उपलब्धियां, आवंटित बजट और भावी योजनाओं का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार किए और कहा कि सपा की सरकार में प्रदेश के बीमारु राज्य बना और निवेश शून्य रहा, लेकिन पौने नौ साल में उप्र देश के टॉप तीन राज्यों में आ गया है। उन्होंने अप्रैल से शिक्षामित्रों को 18 हजार और अनुदेशकों का 17 हजार रुपये मानदेय देने की घोषणा की। बजट पारित होने के साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी ने 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपये के बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को दसवां बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। उन्होंने विपक्ष के वित्तीय स्वीकृतियों पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि स्वीकृतियां समय पर जारी की जाती हैं और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने अपने संबोधन के प्रारंभ में बजट सत्र में सार्थक चर्चा के लिए सत्ता और विपक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया। साथ ही नेता

प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय को दीघार्यु व स्वस्थ रहने की कामना करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ों के साथ घालमेल किया है जो उचित नहीं है। पहली बार उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने को भी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में परिषदीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। अब उन्हें 10 हजार की जगह 18 हजार रुपये हर महीने मिलेगा। इसी प्रकार अनुदेशकों को 17 हजार दिया जाएगा। यह 1 अप्रैल से देय होगा। योगी ने कहा जिन क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय बनाये जाएंगे। इसके लिए 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं इन शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को पांच लाख कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चियों के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालयों को अधिक सशक्त बनाया जाएगा और इसके लिए 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारत मंडपम में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाकः योगी

सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के भारत मंडपम में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन को शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को देश के गौरव के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस आयोजन में दुनिया के 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और वहां पर देश की छवि धूमिल करने का काम युवा कांग्रेस ने किया है। सभी भारतवासियों को इस कृत्य की निंदा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के राजकोषीय घाटे की बात का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष पर चच्चू (शिवपाल यादव) का असर आ गया है, क्योंकि उप्र में 2016-17 में ऋण ग्रस्तता लगभग 30 फीसदी थी। हमने इसे 27 फीसदी किया और 23 फीसदी तक करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय इसी वित्त वर्ष में 1.20 लाख से अधिक हो जाएगी जबकि सपा सरकार में यह मात्र 43 हजार थी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद से कहा कि वे अपनी उम्र के हिसाब से आंकड़ो में घाल-मेल नहीं करेंगे, लेकिन संगत का प्रभाव होता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष यूपी पर उधार की बात बता रहे जो सही नहीं है।

हमने उप्र को बॉटम थ्री से टॉप थ्री राज्यों तक पहुंचाया

मुख्यमंत्री योगी ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2016-17 में उप्र देश के अंदर नीचे से तीसरे नंबर पर था। हालात बहुत खराब थे, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने उप्र को बॉटम थ्री से टॉप थ्री राज्यों तक पहुंचाया है। अब हमारा संकल्प है कि उप्र वन ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने योजना बनाकर अपने बजट से 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया।

वित्तीय प्रबंधन से स्थिति में सुधरीः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया। इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार आ रहा है। हमारा प्रयास चल रहा है कि प्रदेश का पैसा प्रदेश में ही लगे, क्योंकि जिस राज्य के पास एमएसएमई का पावर होगा, वह राज्य अग्रणी होगा।

सीएम अब्दुल्ला ने समयबद्ध भर्ती के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई, इस वर्ष होंगी 30 हजार नियुक्तियां

मुख्यमंत्री ने कहा, 2023 से बिजली शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई

एजेंसी (हि.स.)
जम्मू

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार दोहराया कि उनकी सरकार समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है और घोषणा की कि चालू वर्ष में 30 हजार से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सदस्य प्रो. घरू राम भगत के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि रिक्तियों के मूल्यांकन और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित भर्ती एजेंसियों को समय पर जानकारी भेजने के लिए संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक सेवाओं और जमीनी स्तर के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों में पर्याप्त कर्मचारी संख्या बनाए रखी जाती है। जहां भी आवश्यक हो, स्थापित नियमों के अनुसार अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिक्त पदों को भरने में तेजी लाने के लिए कई उपाय किए हैं।

बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान डॉ. बशीर अहमद शाह वेरी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा को यह भी बताया कि दिसंबर, 2023 से बिजली शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मीटर वाले क्षेत्रों में बिजली की वास्तविक खपत के अनुसार ही बिलिंग की जाती है, जबकि बिना मीटर वाले क्षेत्रों में बिना किसी मनमानी के तय लोड के अनुसार एक समान दर पर बिल बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं से कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों की वसूली नहीं की जाती है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा को सूचित किया कि रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में तीन पर्यटन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और एक परियोजना पूंजीगत व्यय बजट के तहत कुल 307.12 लाख की लागत से प्रगति पर है। उन्होंने सदन को सूचित किया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए पर्यटन विकास योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है। हालांकि, रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2026-27 के लिए नई परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे स्थापित पर्यटन मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य हों, निधियों की उपलब्धता हो और आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हों।

एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए पर्यटन विभाग भी संभाल रहे मुख्यमंत्री ने बताया कि सिद्ध गोरिया मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए पूंजीगत व्यय बजट के तहत 123.41 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों में आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, पार्किंग और शौचालय ब्लॉकों का निर्माण, तालाब का विकास, उच्च स्तंभों पर बत्तियां लगाना और चालू करना तथा संबंधित कार्य शामिल थे। उन्होंने बताया कि परियोजना भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी है।

उन्होंने आगे कहा कि बाबा चामल्याल मंदिर के विकास के लिए पूंजीगत व्यय बजट के तहत 100 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। स्वीकृत कार्यों में फर्श और पगडंडियों का निर्माण, बत्तियां लगाना तथा संबंधित कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विभाग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्लेक्स होर्डिंग्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन और पुस्तिकाओं के माध्यम से सिद्ध गोरिया मंदिर और बाबा चामल्याल मंदिर में वार्षिक मेले का प्रचार करता है। गंगा माता मंदिर, बानू मंदिर और राम मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के संबंध में उन्होंने कहा कि व्यवहार्यता, धन की उपलब्धता और आवश्यक स्वीकृतियों के अधीन भविष्य में इनके विकास पर विचार किया जाएगा।

पांवटा साहिब में प्रस्तावित स्टोन क्रशर का विरोध, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

एजेंसी (हि.स.)
नाहन

सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र में प्रस्तावित एक स्टोन क्रशर को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध तेज कर दिया है। ग्राम पंचायत सैनवाला मुबारकपुर, बेहड़े वाला और आसपास के टोकियों के लोग गुरुवार को नाहन पहुंचे और जिला खनन अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर स्टोन क्रशर प्रस्तावित है, वह एनएच-07 से 100 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। इसके अलावा आसपास सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषि भूमि और आबादी वाला क्षेत्र भी मौजूद है, जो क्रशर शुरू होने पर प्रभावित हो सकते हैं। लोगों ने आशंका जताई कि धूल, शोर और भारी वाहनों की आवाजाही से क्षेत्र के पर्यावरण और जनजीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि रेणुका बांध विस्थापितों के आवास के लिए चयनित भूमि भी प्रस्तावित स्थल के पास है, जिससे भविष्य में बसने वाले परिवारों को परेशानी हो सकती है। स्थानीय निवासी मुकेश कुमार ने कहा कि स्टोन क्रशर की प्रस्तावित भूमि के साथ ही सुंकर खड्ड बहती है, जिसका हाल ही में तटीयकरण किया गया है। उनका कहना है कि यदि क्रशर लगा तो खड्ड के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रस्तावित स्टोन क्रशर की अनुमति पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी आपत्तियों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

विदेशी मेडिकल प्रवेश धोखाधड़ी मामले में ईओडब्ल्यू ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

विदेशी मेडिकल प्रवेश धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

एक बयान में जम्मू-कश्मीर की क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की माननीय अदालत में आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत एफआईआर संख्या 20/2025 में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की है। एक लिखित शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को उसके रिश्तेदार पीरजादा आबिद पुत्र पीरजादा मोहम्मद

नईम निवासी बिजबेहडा आजाद बस्ती नटीपोरा, श्रीनगर ने यूरोप कंसल्टेंसी सेंटर के मालिक सैयद वसीम पुत्र सैयद बशीर अहमद निवासी करीमाबाद पुलवामा, आजाद बस्ती नटीपोरा, श्रीनगर से मिलवाया था। उन्होंने शिकायतकर्ता के बेटे को बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का आश्वासन दिया था। शिकायतकर्ता को सैयद सुहैल एजाज पुत्र सैयद एजाज कादरी निवासी तक्या मागम कोकरनाग, मौजूदा समय में मुस्लिम आबाद नुन्द्रेश कॉलोनी बेमीना के सामने और जैगम खान पुत्र गुलाम मोहम्मद खान निवासी महमदिया कॉलोनी बेमीना श्रीनगर से मिलवाया गया जो ओवरसीज कंसल्टेंसी के मालिक हैं। उनके आश्वासनों पर भरोसा करके शिकायतकर्ता ने पार्क व्यू मेडिकल कॉलेज में लाखों रुपये फीस के रूप में जमा किए। जांच में पता चला कि आरोपियों ने धोखाधड़ी से लाखों रुपये प्राप्त किए लेकिन कॉलेज में केवल 8,000 अमेरिकी डॉलर (2021 की विनिमय दरों के अनुसार लगभग 6.04 लाख रुपये) जमा किए। शेष राशि का भुगतान न करने के कारण छात्र को संस्थान छोड़ने के लिए कहा गया। बैंक रिकॉर्ड, मेडिकल कॉलेज से प्राप्त आधिकारिक सूचना और जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों के आधार पर चारों आरोपियों, अर्थात पीरजादा आबिद पुत्र पीरजादा मोहम्मद नईम निवासी बिजबेहरा आजाद बस्ती नटीपोरा, श्रीनगर; 2. सैयद वसीम पुत्र सैयद बशीर अहमद निवासी करीमाबाद पुलवामा, आजाद बस्ती, नटीपोरा, श्रीनगर, मेसर्स यूरोप कंसल्टेंसी सेंटर के मालिक; सैयद सुहैल एजाज पुत्र सैयद एजाज कादरी निवासी तक्या मगम, कोकरनाग मुस्लिम आबाद नन्द्रेश कॉलोनी बेमीना के सामने; और जैगम खान पुत्र गुलाम मोहम्मद खान निवासी बेमीना श्रीनगर, ओवरसीज कंसल्टेंसी के मालिक के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो चुके हैं।

शिमला नगर निगम का 688 करोड़ का सरप्लस बजट पेश

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

राजधानी शिमला में कांग्रेस शासित नगर निगम का बजट शुक्रवार को पेश किया गया। महापौर सुरेंद्र चौहान ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 688 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष के 188 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी अधिक है। नगर निगम ने इस बार शहरवासियों पर कोई नया कर नहीं लगाया है। बजट में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, महिला सुविधाओं, हरित ऊर्जा और कर्मचारियों के कल्याण पर खास जोर दिया गया है।

महापौर ने घोषणा की कि शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं के लिए सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माताओं की सुविधा के लिए रिज और मॉल रोड पर फीडिंग रूम बनाए जाएंगे। रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम ने शहर में 26 चिन्हित स्थानों पर फूड वैन देने की योजना भी घोषित की है, जिससे बेरोजगार महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार मिल सके। शहर

पार्किंग, ई-कार्ट और सोलर प्रोजेक्ट पर फोकस

के कोर एरिया में ई-कार्ट चलाने की भी योजना है। इससे ट्रैफिक दबाव कम करने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलने की उम्मीद है। पार्किंग समस्या से राहत देने के लिए हर वार्ड में पार्किंग निर्माण और पार्क विकसित करने की बात बजट में कही गई है। महापौर ने शिमला में छह साइकलिंग ट्रैक बनाने की घोषणा भी की। कर्मचारियों के कल्याण के लिए नगर निगम पहली बार बीमा योजना शुरू करेगा, जिसका प्रीमियम कर्मचारियों से नहीं लिया जाएगा। बालूगंज में निगम कर्मचारियों के लिए 34 करोड़ रुपये की लागत से 72 आवास बनाए जाएंगे। बजट में शहर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीसीटीवी लगाने हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा आय बढ़ाने के लिए नगर निगम आवासीय फ्लैट बनाकर बेचने की योजना पर काम करेगा। तारादेवी के पास वर्ल्ड क्लास वेलनेस सेंटर बनाने की घोषणा भी की गई है। सचिवालय से चौड़ा मैदान तक भूमिगत डक्ट बिछाए जा रहे हैं और फाइबर व पाइप डालने के लिए कंपनियों से शुल्क लिया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में भरयाल में दो मेगावॉट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने और सभी वार्डों में एक हजार सोलर लाइटें लगाने की योजना भी बजट में शामिल है। शहर में साइकिल स्टैंड बनाए जाएंगे और खराब पेयजल वाली बावड़ियों के पानी का उपयोग शौचालयों में करने की बात भी कही गई है। हालांकि बजट सत्र के दौरान सदन का माहौल उस समय गरमा गया जब भाजपा पार्षदों ने बजट प्रक्रिया का विरोध शुरू कर दिया। बजट पेश होने से पहले ही सदन में तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा पार्षदों ने मेयर के अधिकारों पर सवाल उठाते हुए बजट को अवैध करार दिया।

भाजपा पार्षदों का कहना है कि महापौर का ढाई वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा एक्ट अभी कानून नहीं बना है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्ताव को राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिली है और मामला न्यायालय में लंबित है।

संक्षिप्त-समाचार

शिवरात्रि शूटिंग मेला में गौरव जमवाल को गोल्ड, घनश्याम ठाकुर को रजत

मंडी। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला शूटिंग प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में गौरव जमवाल ने गोल्ड मेडल जीता जबकि घनश्याम ठाकुर को रजत पदक मिला। घनश्याम जो वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टीजीटी प्राध्यापक के तौर पर तैनात है ने बीते साल इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया था मगर इस बार उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वह वर्ष 2024 की राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भी विजेता रह कर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। गौरतलब है मंडी के गौरव जमवाल व घनश्याम ठाकुर बीते साल राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर पाक ने सीजफायर का किया उल्लंघन

श्रीनगर। पाकिस्तान ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अधिकारियों ने कहा कि कुपवाड़ा (उत्तरी कश्मीर) के नौगाम सेक्टर में टीएमजी (टूट मार गली) में दोपहर के आसपास संघर्ष विराम उल्लंघन हुआ जब पीओके चौकियों ने भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की। कुछ देर बाद गोलीबारी बंद हो गई। उन्होंने आगे बताया कि कोई जानमाल का नुकसान या चोट नहीं आई।

'भार मुक्ति प्रमाण पत्र' न मिलने पर किसानों में रोष, आंदोलन की चेतावनी

नाहन। सिरमौर जिले में किसानों को ह्लभार मुक्ति प्रमाण पत्रह्व जारी न किए जाने से असंतोष बढ़ता जा रहा है। किसानों का कहना है कि यह प्रमाण पत्र भूमि संबंधी कार्यों, बैंक ऋण, फसल ऋण और अन्य राजस्व प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन लंबे समय से यह जारी नहीं हो रहा है। इसके कारण कई किसानों के जरूरी काम अटक गए हैं और उन्हें प्रशासनिक उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है। उधर पटवारी-कानूनगो संघ का कहना है कि इस मामले में यूनियन की ओर से मांग पत्र दिया गया है, इसलिए फिलहाल प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि किसानों का सवाल है कि यदि सरकारी कर्मचारी यूनियन की मांगों का हवाला देकर जनता के काम रोक देंगे तो आम लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहाँ जाएँगे। इस मुद्दे पर हिमाचल किसान सभा के जिला महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने प्रेस वार्ता में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि पटवारी-कानूनगो संघ की कोई जायज मांग है तो प्रशासन को उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसानों को परेशान करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजेंद्र ठाकुर ने प्रशासन से स्पष्ट जवाब माँगा कि किसानों को उनके वैध अधिकारों से आखिर क्यों वंचित किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही किसानों को भार मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए तो संगठन को मजबूरन व्यापक आंदोलन शुरू करना पड़ेगा।

एफआरए के तहत जम्मू-कश्मीर में 41,900 से अधिक वन अधिकार दावे प्राप्त हुए: सरकार

जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को सूचित किया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर भर में कुल 41,944 दावे प्राप्त हुए हैं जिनमें 28,925 व्यक्तिगत वन अधिकार दावे और 13,019 सामुदायिक वन अधिकार दावे शामिल हैं। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006, जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के रूप में भी जाना जाता है का उद्देश्य वन-निवास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देना है जो कम से कम तीन पीढ़ियों से वन भूमि पर रह रहे हैं। विधानसभा में भाजपा विधायक आरएस पठानिया के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, वन मंत्री जावेद राणा ने अधिनियम के तहत प्राप्त दावों का जिलेवार विवरण प्रदान किया। राणा ने कहा कि राजौरी जिले में 16,442 दावों के साथ सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई जिसमें 9,067 आईएफआर और 6,002 सीएफआर दावे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद कुपवाड़ा था जहां 6,039 दावे (5,448 व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) और 591 सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर)) और पुंछ में 5,175 दावे (1,282 आईएफआर और 3,893 सीएफआर) दर्ज किए गए। राणा ने कहा कि बडगाम में 4,065 दावे (3,862 आईएफआर और 203 सीएफआर) दर्ज किए गए जबकि डोडा में 1,795 दावे दर्ज किए गए और शोपियां (1,595), कुलगाम (1,405), रामबन (1,308) और बारामूला (741) दर्ज किए गए।

विद्यार्थियों ने कागज पर उकेरा अपने सपनों का विकसित भारत

सिटी दर्पण संवाददाता
कुनिहार (सोलन)

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), शिमला द्वारा पीएम श्री जवाहर नवोदय स्कूल, कुनिहार में आयोजित दो दिवसीय विकसित भारत चित्र प्रदर्शनी एवं जन सूचना अभियान का शुक्रवार समापन हुआ।

समापन अवसर पर सैकड़ों विद्यार्थियों की मौजूदगी में क्विज प्रतियोगिता हुई जिसमें प्रतिभागी टीमों ने उत्साह से भाग लिया। आज विकसित भारत विषय पर चित्रकला एवं नारा लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए। छठवीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीनियर एवं जूनियर में अलग अलग आयोजित इन स्पधाओं ने बच्चों ने विकसित भारत को लेकर अपनी कल्पना को चित्रों एवं रंगों के जरिए कैनवास पर रच दिया। किसी ने डिजिटल भारत को अपना विषय बनाया तो किसी देश की विभिन्न उपलब्धियों को चित्रित किया। किसी ने अंतरिक्ष में देश की उपलब्धियों को साकार किया तो किसी सड़क नेटवर्क के विस्तार को कागज पर उकेर दिया। चित्रकला प्रतियोगिता में सीनियर श्रेणी में गुनगुन ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि प्रियल और आशुतोष को क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान मिले। वहीं, जूनियर श्रेणी में साक्षी को पहला, निधि को दूसरा एवं चिराग ने तीसरा स्थान मिला। नारा लेखन प्रतियोगिता में भी बच्चों ने गजब की कल्पना शीलता प्रदर्शित की। इस स्पर्धा में सीनियर श्रेणी में भार्गवी, अनुष्का और सूर्यांश को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुए जबकि जूनियर श्रेणी में अयांश को पहला, निशांत को दूसरा एवं जसकरण को तीसरा स्थान मिला।

क्विज प्रतियोगिता में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। स्थिति यह बन गई कि तीन टीमों के बीच स्कोर बराबर रहा और अतिरिक्त प्रश्न पूछकर विजेताओं का चयन किया गया। उदयगिरी हाउस की अक्षिता, प्रयानशिका, अयान और रिवांश की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। जबकि शिवालिक हाउस की देवांगी, निशु, दिलशान एवं प्रशांत की टीम दूसरे स्थान पर रही। तीसरा स्थान नीलगिरी हाउस की इक्षिता, जसप्रीत, देव और विवेक की टीम को मिला।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय कुनिहार के प्राचार्य श्री कृष्ण कुमार यादव थे जबकि उप प्राचार्य अनिता कंवर और केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला के सहायक निदेशक प्रकाश पंत विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे। प्राचार्य श्री यादव ने केंद्रीय संचार ब्यूरो की

विकसित भारत चित्र प्रदर्शनी एवं जन सूचना अभियान को एक सार्थक और सकारात्मक आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि इसतरह के आयोजन विद्यार्थियों के ज्ञान तथा समझ के स्तर को और बेहतर बनाने में सहभागी हैं।

कार्यक्रम में, नवोदय विद्यालय, कुनिहार के शिक्षक, विद्यार्थी, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के सहायक निदेशक संजीव शर्मा और केंद्रीय संचार ब्यूरो, शिमला के अधिकारी- कर्मचारी तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सीबीसी के प्रकाश पंत ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सीबीसी से संबद्ध कलाकारों और स्कूल के विद्यार्थियों की नाटी ने सभी का मन मोह लिया।

इस चित्र प्रदर्शनी और जनसूचना अभियान में भारत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं पहलों के बारे में बच्चों को रोचक शैली में जानकारी दी गई । कार्यक्रम की शुरूआत कल जन जागरूकता रैली से हुई। रैली में स्कूल के 150 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने रैली के जरिए विकसित भारत@2047 के तहत स्वच्छता अभियान और सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में आम लोगों को जागरूक किया गया।

घरेलु विवाद में बुरी तरह से झुलसी महिला ने पीजीआई में तोड़ा दम, पति गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

मंडी जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली उपमंडल के गांव सपलोह की नीलम ठाकुर आखिर जिंदगी की जंग हार गई। उसने शुक्रवार को पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि मंडी सदर थाना में 12 फरवरी को बीएनएस की धारा 109, 83 व 3-5 के तहत यह यह मामला दर्ज हुआ था। आरएफएसएल की टीम व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मौका पर जांच के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने इस मामले में नीलम ठाकुर के पति ठाकर दास पुत्र सुख राम निवासी सपलोह को गिरफ्तार कर लिया था। नीलम के पिता व परिजनों ने मंडी आकर पुलिस अधीक्षक व उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को ससुराल में पति व सास मारपीट किया करते थे और उन्होंने ने ही तेल छिड़क कर उसे जलाया है। बुरी तरह से

जल चुकी नीलम को पहले कोटली, फिर मेडिकल कालेज नेरचौक और फिर हालत गंभीर होने पर पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था जहां पर उसका इलाज चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता को बयान देने हेतू चिकित्सीय रुप से स्वस्थ होने पर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायालय संख्या 24, चंडीगढ़ द्वारा पीड़िता का विधिवत बयान दर्ज किया गया था। अपने बयान में पीड़िता ने इस कृत्य के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराया था। शुक्रवार को उपचार के दौरान पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में पीड़िता की मृत्यु हो गई है। पुलिस के अनुसार मृतका का पोस्टमार्टम पी.जी.आई. चण्डीगढ़ में विधि अनुसार करवाया जा रहा है, फिर भी विषय की गंभीरता को समझते हुए इस प्रकरण में सभी पहलुओं पर गहन एवं निष्पक्ष जांच जारी है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगामी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आरडीजी के मुद्दे पर पूरी भाजपा हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ : उपमुख्य सचेतक

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि भाजपा का आरडीजी पर असली चेहरा प्रदेश के सामने बेनकाब हो चुका है।

विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए आरडीजी बहाल करने के लिए नियम 102 के तहत लाए गए सरकारी प्रस्ताव का विरोध कर भाजपा ने अपना वास्तविक चेहरा उजागर कर दिया है। शुक्रवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने भाजपा नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि आरडीजी के मुद्दे पर एक बार भी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या भाजपा आरडीजी को बंद करने के पक्ष में है या नहीं? उन्होंने कहा कि इससे पहले आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक सहायता देने संबंधी विधानसभा प्रस्ताव का भी भाजपा विधायकों ने समर्थन नहीं किया था। प्रदेश की जनता देख चुकी है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश के अधिकारों के लिए कभी खड़ी नहीं होती।

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता प्रदेश की जनता को स्पष्ट करें कि कुछ ही महीनों में उनका रुख क्यों बदल गया है। आखिर क्यों आज वह और पूरी भाजपा हिमाचल प्रदेश के हितों के खिलाफ खड़ी है? कांग्रेस सरकार का विरोध करते-करते भाजपा नेतृत्व शायद प्रदेश के लोगों के हितों को भूल चुका है। भाजपा नेता आज केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाली धनराशि को आर्थिक मदद के रूप में गिना रहे हैं, जबकि यह प्रदेश की जनता का अधिकार है। इस प्रकार के बेतुके स्पष्टीकरण प्रदेश के लोगों के गले नहीं उतरने वाले।

शिक्षा | **शिक्षा विभाग में 7 हजार पदों पर रेगुलर नियुक्तियां: रोहित ठाकुर**

शिक्षा मंत्री ने किया नव निर्मित स्कूल भवनों का लोकार्पण

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

मंडी जिला के सदर विधान सभा क्षेत्र के कोटमोर्स और मझवाड़ के दौरे के दौरान आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नव निर्मित स्कूल भवनों के लोकार्पण किए। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटमोर्स में 71 लाख रुपए की लागत और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मझवाड़ में 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित स्कूल भवन का लोकार्पण किया।

उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और गुणात्मक शिक्षा की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे है। शिक्षा मंत्री ने कहा राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 148 स्कूलों की

सीबीएसई बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राजकीय स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार राजकीय स्कूलों के मेधावी बच्चों और अध्यापकों को एक्सपोजर विजिट करवाया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 350 से अधिक अध्यापकों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की साक्षरता दर 99.33 प्रतिशत हो गई है जो देश भर में सबसे अधिक है। जब की राज्य के गठन के समय राज्य की साक्षरता दर मात्र 7 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि रीडिंग के मामले में प्रदेश केरल से बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश से शिक्षा विभाग और निदेशालय को एकीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में 7 हजार पदों पर रेगुलर नियुक्तियां की गई। 4 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया राज्य चयन आयोग के माध्यम से जारी है जिन्हें शीघ्र भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभाग में शिक्षक और गैर शिक्षकों के लगभग 10 हजार पदों पर पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं जिसमें उप निदेशक तक के पद शामिल है, जो लबे समय से रुकी हुई थी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार एक साथ रिकॉर्ड 802 पदों पर प्रधानाचार्यो की पदोन्नति की गई है। उन्होंने कहा कि मंडी कॉलेज प्रदेश के सबसे पुराने महाविद्यालयों में से एक है और इस महाविद्यालय के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए लगभग 16 करोड़ 45 लाख रुपए की धन राशि उपलब्ध करवाई गई है। महाविद्यालय निर्माण पर अब तक 45 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष धन राशि शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन शिक्षण संस्थानों, जिनका कार्य 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है उन्हें जल्द शेष बजट उपलब्ध करवा कर पूरा किया जाएगा।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एंव संपादक भुपेंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट न. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एंव 801/1 सेक्टर-40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्कः 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत सर्वसम्मति, संविधान और जनसेवा के संकल्प के साथ

एकता, राष्ट्रभक्ति और 'सबका साथझ्रसबका विकास' राज्य की विकास यात्रा का मार्गदर्शन करेंगे: राज्यपाल

अंत्योदय और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: राज्यपाल

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा विधानसभा के 15वें विधानसभा सत्र के बजट सत्र के प्रथम दिन आज सदन को संबोधित करते हुए हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार राजनीतिक शक्ति को जनसेवा का माध्यम मानती है और इसे समाज के अंतिम एवं सबसे निचले पायदान पर खड़े परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने में समर्पित भाव से उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट सत्र सार्थक विचार-विमर्श और संवाद के माध्यम से ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बनेगा। राज्यपाल ने पुनः दोहराया कि सरकार गरीबों के जीवन स्तर में सुधार, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तथा प्रत्येक नागरिक को गरिमा, सुरक्षा और अवसर सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय गीत, 'वंदे मातरम्' के हाल ही में 150 वर्ष पूरे हुए हैं। यह गीत भारत की आत्मा है और भारत माता के प्रति हमारे समर्पण की अमर गाथा है। हरियाणा की धरा हमेशा से राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत रही है। 'वंदे मातरम्' का भाव हमारी संस्कृति, लोकगीतों और जीवनशैली में सहज रूप से समाया हुआ है। देश भर में हमारे राज्य के लोगों को खाद्य सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और ओलंपिक मेडल दिलाने के लिए सराहा जाता है। हमारे किसान, सैनिक और खिलाड़ी हमेशा 'वंदे मातरम्' की भावना से प्रेरित होते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के जीवन को बेहतर बनाना, किसानों की आय बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना और महिलाओं का सम्मान व सुरक्षा सुनिश्चित करना ही देश की सच्ची सेवा तथा 'वंदे मातरम्' की सच्ची अभिव्यक्ति है।

प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिए गए मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' को सुशासन का आधार बनाया है। यह हम सबका सपना है कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा, तब तक यह एक विकसित, आत्मनिर्भर और दुनिया में सबसे आगे रहने वाला देश होगा। इस राष्ट्रीय संकल्प में हरियाणा की भूमिका बहुत अहम होगी। इसलिए, 'हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047' तैयार किया है। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट का लोकार्पण गत 24 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा पंचकूला में किया गया। यह डॉक्यूमेंट वर्ष 2047 तक हरियाणा को एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था के रूप में दृढ़ता से स्थापित करने के लिए रणनीतिक ब्लूप्रिंट है। इस डॉक्यूमेंट में 'विकसित हरियाणा' बनाने के लिए छः मुख्य संकल्प हैं।

राज्यपाल ने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का 'अंत्योदय दर्शन' संवेदनशील शासन की नैतिक प्रतिबद्धता है। इस मार्ग पर चलते हुए सोशल सिक्योरिटी पेंशन अब प्रो-एक्टिव मोड में दी जा रही हैं। परिवार पहचान पत्र के डेटा के जरिए योग्य लाभार्थियों की पहचान की जाती है और बिना किसी एप्लीकेशन या सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाए पात्रता होने पर पेंशन स्वतः शुरू हो जाती है। हरियाणा देश में सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाले राज्यों में से एक है। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को हर महीने 3,200 रुपये मिलते हैं। खास बात यह है कि दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम-2016 के तहत दिव्यांगता की सभी 21 कैटेगरी को पेंशन स्कीम में शामिल किया गया है। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय मदद भी दी जा रही है।

असीम कुमार घोष ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' को प्रभावी रूप से लागू किया है। इस योजना के तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की सहायता दी जा रही है, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। साथ ही, अब उन माताओं को भी योजना में शामिल किया गया है जो अपने बच्चों की शिक्षा, पोषण और शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित कर रही हैं। अब तक 9 लाख 22 हजार 452 लाभार्थी बहनों के खातों में 4 किस्तों में 634 करोड़ रुपये की राशि डाली जा चुकी है।

हरियाणा सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सरप्लस-राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है : राज्यपाल

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सरप्लस राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वर्ष 2020-21 से पूरे राज्य में 4,818 करोड़ रुपये की लागत से 223 नए सब-स्टेशन बनाए गए हैं और 1,302 किलोमीटर लंबी नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं। प्रोफेसर असीम कुमार घोष शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर अपना अभिभाषण दे रहे थे। राज्यपाल ने ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि कुशल प्रबंधन से सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां (AT&C) वर्ष 2014-15 के 30 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में केवल 9.48 प्रतिशत रह गई हैं। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के विजन के अनुरूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2025 को यमुनानगर में 7,272 करोड़ रुपये की लागत वाली 800 टह की अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल यूनिट की नींव रखी, जो हमारी भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि 'म्हारा गांव- जगमग गांव' योजना के तहत, 6,019 गांवों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत 55,157 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं। हमारा लक्ष्य दिसंबर, 2027 तक सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित करना है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2014-15 से अब तक लगभग 3.13 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए गए हैं। यह वर्ष 2004 से 2014 के पिछले 10 सालों में जारी किए गए 1 लाख 69 हजार 226 नए ट्यूबवेल कनेक्शन से काफी अधिक हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1,88,116 सोलर पंप लगाकर हरियाणा आज देश में दूसरे स्थान पर है। प्रोफेसर घोष ने बताया कि गांवों में बड़े पैमाने पर सोलर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जा रही हैं। ये प्रयास हरियाणा को एक साफ, हरा-भरा और ऊर्जा सुरक्षित राज्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

अन्नदाता के सम्मान से प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है : राज्यपाल

हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने और उनके जोखिम को न्यूनतम करने के लिए बहुआयामी रणनीतियां अपनाई हैं। अन्नदाता के सम्मान से प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर अपना अभिभाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने और संसाधनों का दक्षता से वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान रबी सीजन के दौरान 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल को इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एकीकृत करने से उर्वरक वितरण की पारदर्शिता में सुधार हुआ है। गत 8 अक्टूबर, 2025 से 11 फरवरी, 2026 के बीच यूरिया की खपत 1 लाख 28 हजार 231 मीट्रिक टन और डी.ए.पी. की खपत 24 हजार 168 मीट्रिक टन कम हुई है। इससे केंद्र सरकार को उर्वरकों पर सब्सिडी के तहत 716 करोड़ रुपये की बचत हुई। राज्यपाल ने कहा कि मृदा की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 10 हजार 36 किसानों ने प्राकृतिक खेती पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है और उनमें से 7 हजार 580 किसान 18 हजार 559 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा, 163 गांवों में 1 लाख 58 हजार एकड़ लवणीय और जलभराव वाली भूमि का सुधार करके इसे खेती योग्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को जोखिमों से बचाने के लिए, खरीफ-2016 से 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत 9 हजार 243 करोड़ रुपये के क्लेम दिए गए हैं। 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत, 21 किस्तों में 7 हजार 235 करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में सीधे डाले गए हैं। पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए, फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 9 हजार 885 मशीनें सब्सिडी पर दी गई हैं। यह हर्ष की बात है कि 5 लाख 54 हजार किसानों को दिए गए 461 करोड़ 75 लाख रुपये के प्रोत्साहन से वर्ष 2025 के दौरान फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 52.9 प्रतिशत की कमी आई है। प्रोफेसर घोष ने कहा कि गन्ना पिराई सीजन 2025-26 के लिए 415 रुपये प्रति क्विंटल का राज्य सुझावित मूल्य तय किया गया है।

'प्रदेश सरकार 'नारी शक्ति' को राज्य के सर्वांगीण विकास का आधार मानती है'

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि हरियाणा सरकार 'नारी शक्ति' को राज्य के सर्वांगीण विकास का आधार मानती है और उनके सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर अपना अभिभाषण दे रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति का सबसे सशक्त संकेत महिलाओं की स्थिति से मिलता है। हरियाणा सरकार महिला सशक्तिकरण को महिलाओं में नेतृत्व और निर्णय क्षमता के विकास के रूप में देखती है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 'ड्रोन दीदी योजना' के तहत ग्रामीण महिलाओं को राज्य स्वामित्व वाली कंपनी 'ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ हरियाणा लिमिटेड' के माध्यम से 29 सितंबर, 2021 से स्टेट-ऑफ-द-आर्ट स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें 33 'ड्रोन दीदियों' को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 15 का प्रशिक्षण जारी है। इनके अतिरिक्त, लगभग 1,350 'ड्रोन दीदियों' के लिए जल्द ही प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। उन्होंने महिला सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए बताया कि राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में, 33 महिला पुलिस थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। इनके अलावा, अगले वर्ष 7 नए महिला पुलिस थाने - लोहारू, बरवाला (हिसार), नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पेहोवा में खोलने का निर्णय किया गया है। प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए उदाहरणीय प्रयास किए हैं।

'हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी'

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि युवा शक्ति नवाचार के माध्यम से 'विकसित भारत- विकसित हरियाणा' के विजन को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। हरियाणा सरकार ने भी युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर अपना अभिभाषण दे रहे थे। प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने युवा शक्ति को हरियाणा का भविष्य बताते हुए कहा कि हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा वर्ग है। यह वही युवा शक्ति है, जो खेतों में परिश्रम करती है, खेल के मैदानों में देश का नाम रोशन करती है और नवाचार के माध्यम से 'विकसित भारत- विकसित हरियाणा' के विजन को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी है। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं और युवाओं में आत्मविश्वास जगा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। इसके द्वारा अब तक लगभग 1 लाख 18 हजार संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इन युवाओं को न सिर्फ.रोजगार मिला है, बल्कि उन्हें सेवा अवधि की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ, चिकित्सा और जीवन बीमा सुरक्षा देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने खुद को एक अधिकृत भर्ती एजेंसी के रूप में भी पंजीकृत किया है और विदेशी नियोक्ताओं के साथ तालमेल भी बनाया है।

हरियाणा सरकार ने सड़कों, परिवहन, शहरी सुविधाओं और डिजिटल ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है : घोष

हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सड़कों, परिवहन, शहरी सुविधाओं और डिजिटल ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है क्योंकि किसी भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की मजबूत नींव होता है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर अपना अभिभाषण दे रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के बिना सतत विकास संभव नहीं है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान 6,030 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। चालू वित्त वर्ष में 68 किलोमीटर लंबी नई सड़कें भी बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य की सभी 12 फुट चौड़ी सड़कों को 18 फुट चौड़ा करने का फैसला लिया है। इस दिशा में, मार्च, 2026 तक 1,275 किलोमीटर लंबी सड़कों का काम पूरा हो जाएगा और शेष 2,225 किलोमीटर लंबी सड़कों का काम मार्च, 2027 तक पूरा हो जाएगा। सरकार का विजन स्पष्ट है कि राज्य का हर ज़िला सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा होना चाहिए, जिससे सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि शहरी जीवन को आसान और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड एक नई क्रांति ला रही है। वर्तमान में 10 बड़े शहर रोहतक, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, हिसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला तथा करनाल में सिटी बस सेवा उपलब्ध है और यहां 65 इको-फ्रेंडली ई-बसें सड़कों पर चल रही हैं। परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए, पानीपत में एक इलेक्ट्रिक बस डिपो बनकर तैयार हो गया है और यमुनानगर-जगाधरी में आगामी 31 मार्च, 2026 तक डिपो बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा, गुरुग्राम व फरीदाबाद जैसे महानगरों और 10 अन्य शहरों के लिए 650 स्टैंडर्ड फ्लोर अउ बसें शुरू की जा रही हैं, जो शहरी परिवहन को नई परिभाषा देगा। राज्यपाल ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए 11,607 करोड़ रुपये की लागत का 'हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर' गेम-चेंजर साबित होगा। इसका प्राथमिक सेक्शन, पातली-मानेसर, माल गाड़ियों के लिए खोला जा चुका है और पूरे प्रोजेक्ट को जून, 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही, हम सड़कों पर सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए लेवल क्रॉसिंग खत्म कर रहे हैं। अब तक विभिन्न रेलवे ट्रैक्स पर 100 रोड ओवर ब्रिज (फ्ङ्ग) और रोड अंडर ब्रिज (फ्न्ड्ग) बनाए जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी दी कि हवाई क्षेत्र में हिसार एक मुख्य हब बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2025 को हिसार-अयोध्या-हिसार रूट पर उड़ान सेवा का औपचारिक उद्घाटन किया था। यह सरकार की आस्था और विकास के संगम को प्रदर्शित करता है। अब तक लगभग 4,000 श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं। हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और जयपुर के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। ग्रामीण विकासः गांवों से विकास की धारा प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने राज्य में ग्रामीण विकास के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा के गांव इसकी आत्मा हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सम्मानजनक जीवन स्तर को लक्ष्य बनाया है। डिजिटल सेवाओं को गांवों तक पहुंचाकर प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।

पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व: विजय नड्डा

सिटी दर्पण संवाददाता

कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के अंतर्गत इको क्लब द्वारा 'पंच परिवर्तन' विषय पर पर्यावरण व्याख्यान माला का आयोजन पर्यावरण विज्ञान संस्थान के प्रथम तल स्थित सेमिनार हॉल में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही।

मुख्य वक्ता के रूप में विद्या भारती (उत्तर क्षेत्र) के संगठन मंत्री विजय नड्डा ने 'पंच परिवर्तन' की अवधारणा को विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी नीतियों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली से जुड़ा हुआ दायित्व है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलसचिव लेफ्टिनेंट (प्रो.) वीरेन्द्र पाल ने की। इको क्लब के नोडल अधिकारी प्रो. ए. आर. चौधरी ने अपने स्वागत भाषण में व्याख्यान माला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस पहल का लक्ष्य परिसर को हरित एवं स्वच्छ बनाने के साथ-साथ विद्यार्थियों में पर्यावरणीय नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। कार्यक्रम में पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया तथा विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई। मंच संचालन डिप्टी ईएनओ डॉ. मीनाक्षी सुहाग व धन्यवाद ज्ञापन डॉ. हरदीप ने किया। डिप्टी ईएनओ प्रो. दीपक राय बब्बर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्रो. परमेश कुमार, प्रो. निरूपमा भट्टी, प्रो. कुसुमलता, प्रो. नीरा राघव, प्रो. दीपक राय बब्बर, डॉ. मीनाक्षी सुहाग, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. पूजा, डॉ. हरदीप, डॉ. संदीप गुप्ता, डॉ. रमेश कुमार, डॉ. सौरभ चौधरी, डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. हरिप्रकाश, डॉ. दीप्ति सहित शिक्षक, शोधार्थी व विद्यार्थी मौजूद रहे।

अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के प्रदेश सचिव राजेश सिंगला के आवास पर पहुंचे सांसद नवीन जिंदल

कुरुक्षेत्र। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा के प्रदेश सचिव राजेश सिंगला के आवास पर शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के सांसद एवं देश के विख्यात उद्योगपति नवीन जिंदल पहुंचे। इस मौके पर सिंगला परिवार ने सांसद नवीन जिंदल का स्वागत किया। सांसद जिंदल ने कहा कि उनके परिवार के राजेश सिंगला से काफी पुराने संबंध हैं। राजेश सिंगला उनके पिता ओम प्रकाश जिंदल के समय जुड़े हुए हैं। इस मौके पर सांसद ने राजेश सिंगला की बेटी डा. श्रेया अग्रवाल को आशीर्वाद दिया। उल्लेखनीय है कि डा. श्रेया का डा. साहिल से विवाह हो रहा है। इस मौके पर सांसद नवीन जिंदल काफी समय तक विष्णु कालोनी में राजेश सिंगला के आवास पुन्नी कॉटेज में रहे और परिवार के साथ समय बिताया व शुभकामनाएं दी।

सहकारी समिति के सैल्समैन को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

सिटी दर्पण संवाददाता

रोहतक/सोनीपत

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक की टीम ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए सहकारी समिति गांव भैंसवाल कालां, जिला सोनीपत में कार्यरत सैल्समैन सुभाष (उम्र 56 वर्ष) निवासी गांव कटवाल, जिला सोनीपत को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक में अभियोग संख्या 05 दिनांक 20.02.2026, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता, जो खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, ने ब्यूरो को दी गई शिकायत में बताया कि उनके पास लगभग 3 एकड़ भूमि है तथा उन्होंने सहकारी समिति भैंसवाल से एमसीएल कार्ड बनवाया हुआ है, जिसकी ऋण सीमा 60,000 रुपये निर्धारित है। शिकायतकर्ता उक्त सीमा को बढ़वाना चाहता था। 17 फरवरी 2026 को जब वह इस संबंध में सहकारी समिति भैंसवाल में सैल्समैन सुभाष से मिला, तो आरोपी ने एमसीएल कार्ड की सीमा बढ़ाने की एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की। बातचीत के उपरांत 10,000 रुपये में सौदा तय हुआ। शिकायत प्राप्त होने पर ब्यूरो द्वारा कानूनी कार्रवाई करते हुए निरीक्षक जगजीत सिंह, उप-केन्द्र सोनीपत के नेतृत्व में रेडिंग टीम गठित की गई। योजनाबद्ध कार्रवाई के दौरान आरोपी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से बरामद राशि को नियमानुसार जब्त किया गया है तथा मामले की गहन जांच जारी है।

डॉ. ए.एस. चावला, निदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निष्पक्ष एवं गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य करने की एवज में रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 या हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दें।

हरियाणा के विभिन्न आवास पक्षी संरक्षण में बहुत जरूरी: अरविंद यादव

सिटी दर्पण संवाददाता

कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के ईको क्लब द्वारा 'हरियाणा की पक्षी विविधता एवं उसका संरक्षण' विषय पर पर्यावरण विस्तार व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंटल स्टडीज के सेमिनार हॉल में किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेजर जनरल अरविंद यादव ने हरियाणा में पाई जाने वाली विभिन्न पक्षी प्रजातियों, उनके प्राकृतिक आवास, प्रवास चक्र, प्रजनन व्यवहार तथा संरक्षण की चुनौतियों पर विस्तृत एवं तथ्यात्मक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. ए.आर. चौधरी ने की। मंच का संचालन प्रो. दीपक राय बब्बर ने किया व अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन डॉ. मीनाक्षी सुहाग ने किया।कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पक्षी संरक्षण, जैव-विविधता प्रबंधन तथा स्थानीय स्तर पर किए जा सकने वाले प्रयासों से संबंधित अपने विचार एवं जिज्ञासाएं साझा कीं। समग्र रूप से यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने तथा युवाओं को हरित भविष्य के निर्माण हेतु प्रेरित करने की दिशा में एक सार्थक एवं सफल पहल सिद्ध हुआ। इस अवसर पर डीन आफ कॉलेजिज प्रो. ब्रजेश साहनी, प्रो. दीपक राय बब्बर, डॉ. मीनाक्षी सुहाग, डॉ. पूजा, डॉक्टर संदीप सहित विभिन्न विभागों के प्राध्यापकगण, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सम्मान हरियाणा विज्ञान रत्न, युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार समारोह आयोजित

हरियाणा कर रहा 11 प्रख्यात वैज्ञानिकों का सम्मान

28 फरवरी को लोक भवन में होगा वैज्ञानिक पुरस्कार समारोह

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

हरियाणा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा 28 फरवरी को हरियाणा लोक भवन में हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार एवं हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में 11 प्रख्यात वैज्ञानिकों का सम्मान किया जा रहा है।

सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि होंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समारोह की अध्यक्षता करेंगे। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे।

5 वैज्ञानिकों को मिलेंगे हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार

उन्होंने बताया कि हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार में वर्ष 2022 के लिए सीएसआईआर भावनगर के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डा. अरविन्द कुमार व पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के प्राध्यापक डा. राजकुमार, वर्ष 2023 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी से सम्मानित आईआईएसईआर, मोहाली और एमेरिटस पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ की प्राध्यापक डा. सुदेश कौर खंडूजा को तथा वर्ष 2024 के लिए क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र फरीदाबाद के प्राध्यापक डा. दीपक थंकप्पन नायर व राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र मानेसर के वैज्ञानिक डा. अनिर्बान बासू को सम्मानित किया जाएगा।

हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए 6 वैज्ञानिक चयनित

प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार में वर्ष 2022 के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के सहायक प्राध्यापक डा. विनीत वशिष्ट व डी वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डा. विकास, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला के सहायक प्राध्यापक डा. परमवीर सिंह व भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर के सहायक प्राध्यापक डा. चिराग जैन तथा वर्ष 2024 के लिए आईआईएसईआर, मोहाली के सहायक प्राध्यापक डा. जोगेन्द्र सिंह एवं एलवीप्रसाद नेत्र संस्थान हैदराबाद की परामर्शदाता नेत्र चिकित्सक डा. स्वाति सिंह वैज्ञानिक को पुरस्कृत किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह में वर्ष 2022 से 2024 तक के पुरस्कारों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए 5 वैज्ञानिक तथा हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार 6 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है।

हरियाणा के तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मिलेगा आईआईटी स्तर का मार्गदर्शन: महीपाल ढांडा

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़

आईआईटी रुड़की के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की (आईआईटी रुड़की) के साथ 20 फरवरी, 2026 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन राज्य के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि यह समझौता राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं बहुतकनीकी संस्थानों में शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान एकीकरण, संकाय विकास और नवाचार आधारित शिक्षण को नई गति प्रदान करेगा।

इस समझौता ज्ञापन पर आईआईटी रुड़की की ओर से प्रो. विवेक कुमार मलिक, डीन (प्रायोजित अनुसंधान एवं औद्योगिक परामर्श) तथा हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से प्रभजोत सिंह महानिदेशक तकनीकी शिक्षा, हरियाणा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त आईआईटी रुड़की इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं उन्नत अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक ख्याति रखता है। इस सहयोग से हरियाणा के राज्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों (एसआईईटीएस) राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों तथा तकनीकी विश्वविद्यालयों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

यह समझौता आईआईटी रुड़की और तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच एक सशक्त शैक्षणिक सेतु स्थापित करेगा, जिससे प्रदेश के विद्यार्थियों और शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का लाभ प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताओं में संकाय विकास एवं क्षमता निर्माण के अंतर्गत संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संरचित ज्ञान-साझाकरण पहलें शामिल हैं। छात्र प्रशिक्षण एवं परियोजना-आधारित शिक्षण के तहत संस्थागत नियमों के अनुरूप आईआईटी रुड़की में प्रशिक्षण और अनुसंधान के अवसर उपलब्ध होंगे।

इसके अतिरिक्त संयुक्त अनुसंधान, संकाय विनिमय और शैक्षणिक संसाधनों के साझा उपयोग के माध्यम से अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हैकाथॉन, इन्क्यूबेशन कार्यक्रम, स्टार्ट-अप मार्गदर्शन तथा प्रौद्योगिकी आधारित पहलों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा विनीत गर्ग के मार्गदर्शन तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल प्रदेश को तकनीकी नेतृत्व की दिशा में अग्रसर करेगी। यह समझौता गैर-वित्तीय एवं गैर-बाध्यकारी प्रकृति का है तथा पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जो भविष्य में परियोजना-विशिष्ट सहयोग के लिए एक संरचित एवं लचीला ढांचा प्रदान करेगा। इस अवसर पर डॉ. वाई.पी.एस. बरवाल, निदेशक तकनीकी शिक्षा, अनिल कुमार, अतिरिक्त निदेशक प्रो. अमित अग्रवाल, एसोसिएट डीन कॉर्पोरेट इंटरैक्शन (एडीसीआई) आईआईटी रुड़की सहित तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

संपादकीय एआई की नई विश्व व्यवस्था: पैक्स सिलिका में शामिल होकर भारत ने टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाई

भारत और वैश्विक प्रौद्योगिकी साझेदारी के परिदृश्य में एक नया अध्याय तब जुड़ गया जब इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान देश ने औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका गठबंधन में प्रवेश किया। यह कदम केवल एक कूटनीतिक या औद्योगिक समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उभरती कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में रणनीतिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल के माध्यम से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी, सेमिकंडक्टर और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को नया आयाम मिला है, जिससे भविष्य की तकनीकी प्रतिस्पर्धा में लोकतांत्रिक देशों की सामूहिक भागीदारी मजबूत होती दिखाई दे रही है। यह गठबंधन मूलतः उन राष्ट्रों का समूह है जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से लेकर चिप निर्माण और एआई तैनाती तक पूरे ह्लसिलिकॉन स्टैकह्व की सुरक्षा और विविधीकरण सुनिश्चित करना चाहते हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अत्यधिक केंद्रीकरण, आर्थिक दबाव और भू-राजनीतिक निर्भरता जैसे जोखिमों को कम करने के लिए इसे एक दीर्घकालिक रणनीतिक प्लेटफॉर्म के रूप में परिकल्पित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल तकनीकी संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा को एक साथ जोड़ते हुए भविष्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का आधार तय कर सकती है। हस्ताक्षर समारोह के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे भविष्य निर्माण की दिशा में ठोस कदम बताते हुए कहा कि देश केवल सम्मेलन आयोजित नहीं कर रहा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसरों की नींव रख रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक यात्रा का उल्लेख करते हुए चक्रवृद्धि विकास की शक्ति पर जोर दिया और सेमिकंडक्टर क्षेत्र में उभरती संभावनाओं को रेखांकित किया। उनके अनुसार भारतीय इंजीनियर आज दुनिया की अत्याधुनिक दो-नैनोमीटर चिप डिजाइन क्षमता में योगदान दे रहे हैं और उद्योग को आने वाले वर्षों में लाखों कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जो रोजगार और कौशल विकास के लिए व्यापक अवसर पैदा कर सकता है।समारोह में मौजूद अमेरिकी अधिकारी जैकब हेलबर्ग ने इस साझेदारी को साझा भविष्य का रोडमैप बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है और तकनीकी निर्भरता को रणनीतिक हथियार बनने से रोकना जरूरी है। उनके वक्तव्य में यह संकेत स्पष्ट था कि भविष्य के संसाधनों–चाहे वे पृथ्वी के भीतर मौजूद खनिज हों या प्रयोगशालाओं में विकसित एआई एल्गोरिद्म–की सुरक्षा वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी।भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी गठबंधन में भारत की भागीदारी को रणनीतिक आवश्यकता बताया। उनके अनुसार यह साझेदारी उन क्षेत्रों को सुरक्षित करने का प्रयास है जो 21वीं सदी की आर्थिक संरचना तय करेंगे–खनन से लेकर चिप निर्माण और डेटा केंद्रों तक। उन्होंने इस सहयोग को स्वतंत्र समाजों की तकनीकी नेतृत्व क्षमता बनाए रखने के प्रयास के रूप में रेखांकित किया और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित साझेदारी बताया। समझौते के बाद आयोजित उच्च स्तरीय वार्ता में तकनीकी उद्योग और नीति जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने एआई और सेमिकंडक्टर क्षेत्र के तालमेल पर जोर दिया। इस चर्चा में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एस कृष्णन के साथ उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल थे। संजय मेहरोत्रा, जो माइक्रॉन टेक्नॉल्जी के प्रमुख हैं, ने सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण को भविष्य के तकनीकी विकास के लिए अनिवार्य बताया। वहीं रणधीर ठाकुर ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से इस पहल को समयोचित कदम बताते हुए कहा कि सेमिकंडक्टर उद्योग का विकास सदैव सामग्री, नवाचार और कंप्यूटिंग क्षमता के संतुलन से संचालित होता रहा है। इस साझेदारी का व्यापक प्रभाव केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा। नीति विश्लेषकों के अनुसार इससे भारत को वैश्विक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित होने का अवसर मिलेगा। एआई, सेमिकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों में समन्वित निवेश देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था के अगले चरण में अग्रणी स्थान दिला सकता है। साथ ही, यह पहल घरेलू विनिर्माण, अनुसंधान निवेश और कौशल विकास को गति देने में सहायक हो सकती है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे।वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां तकनीकी प्रतिस्पर्धा भू-राजनीतिक प्रभाव का प्रमुख साधन बन चुकी है, ऐसे में यह समझौता संकेत देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीकों का भविष्य आकस्मिक विकास पर नहीं छोड़ा जाएगा। बल्कि इसे साझेदारी, रणनीतिक योजना और साझा मूल्यों के आधार पर निर्मित किया जाएगा। भारत का इस गठबंधन में शामिल होना इस बात का संकेत है कि देश न केवल तकनीकी उपभोक्ता के रूप में बल्कि वैश्विक नवाचार व्यवस्था के सक्रिय निमार्ता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।समग्र रूप से देखा जाए तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हुआ यह समझौता भविष्य के डिजिटल और औद्योगिक परिदृश्य में भारत की रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला कदम साबित हो सकता है। यह सहयोग न केवल आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को नई दिशा देगा बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आने वाले वर्षों में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नीति, उद्योग और नवाचार तंत्र किस तरह मिलकर इन संभावनाओं को ठोस परिणामों में बदलते हैं।

भाषाई विविधता का भविष्य: युवाओं की भूमिका निर्णायक

योगेश कुमार गोयल (हि.स)

मातृभाषा की मदद से न केवल क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जानने-समझने में सहायता मिलती है बल्कि एक-दूसरे से बातचीत करना भी आसान हो जाता है। यही वजह है कि भाषा की विविधता को विस्तार से जानने के लिए कई देशों ने इस विषय पर मिलकर काम करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत एक क्षेत्र का व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति की मातृभाषा को न केवल जान पाएगा बल्कि उसे सीख भी सकेगा।

मानव जीवन में भाषा महत्व को देखते हुए यूनेस्को द्वारा हर साल 21 फरवरी को वैश्विक स्तर पर 'अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' मनाता जाता है। विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति व बौद्धिक विरासत की रक्षा करने, भाषायी तथा सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषावाद का प्रचार करने और दुनियाभर की विभिन्न मातृभाषाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनके संरक्षण के लिए यह उत्सव मनाने का दिवस है। साथ ही यह भाषाओं की विविधता और बहुभाषिता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी समय है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का एक महत्वपूर्ण कारण बहुभाषिता को बढ़ावा देना भी है। बहुभाषिता एक से अधिक भाषा बोलने की क्षमता है, जो कई मायनों में फायदेमंद हो सकती है। यह लोगों को विभिन्न संस्कृतियों को समझने में मदद कर सकती है और उन्हें बेहतर संचारक भी बना सकती है।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष एक महत्वपूर्ण थीम के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय है 'बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की राय', जो भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की रक्षा, पुनर्जीवन और उपयोग में युवाओं की आवश्यक भूमिका को उजागर करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षा प्रणाली समावेश को बढ़ावा देने के लिए शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं को पहचानती और उनका समर्थन करती है। 2025 में यह दिवस 'भाषाएं मायने रखती हैं: अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह' विषय के साथ मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 और 2023 की थीम क्रमशः 'बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है' तथा 'बहुभाषी शिक्षा: शिक्षा को बदलने की आवश्यकता' थी। इससे पहले 2022 की थीम 'बहुभाषी शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग: चुनौतियाँ और अवसर' थी, जबकि 2021 के मातृभाषा दिवस की थीम थी 'शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को प्रोत्साहन'।

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। यूनेस्को द्वारा मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा 17 नवम्बर 1999 को की गई थी और पहली बार वर्ष 2000 में इस दिन को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया था। सही मायनों में इस दिवस को मनाए जाने की शुरूआत अपनी मातृभाषा के लिए बांग्ला भाषा बोलने वालों के प्यार के कारण ही हुई थी। 21 फरवरी को ही यह दिवस मनाए जाने का सुझाव कनाडा में रहने वाले बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम ने दिया था, जिन्होंने बांग्ला भाषा आन्दोलन के दौरान ढाका में 1952 में हुई नृशंस हत्याओं को स्मरण करने के लिए यह दिन प्रस्तावित किया था। भाषा के इस बड़े आन्दोलन में मारे गए युवाओं की स्मृति में ही यूनेस्को द्वारा वर्ष 1999 में निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 21 फरवरी को दुनियाभर में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

विश्वभर में इस दिन अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर भाषा तथा संस्कृति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और शिक्षा तथा साहित्य से जुड़े लोग विभिन्न भाषाओं को लेकर चर्चा करने के साथ-साथ किसी भी भाषा को सरल व सुगम बनाने के लिए परामर्श भी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनियाभर में बोली जाने वाली करीब सात हजार भाषाओं में से 90 प्रतिशत भाषाएं बोलने वाले लोग एक लाख से भी कम हैं। चिंता की बात यह है कि दुनियाभर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में से अब 40 प्रतिशत से अधिक भाषाएं लुप्तप्राय हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक केवल कुछ सौ भाषाओं को ही शिक्षा प्रणालियों और सार्वजनिक क्षेत्र में जगह मिली है और वैश्विक आबादी के करीब 40 प्रतिशत लोगों ने ऐसी भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं की, जिसे वे बोलते अथवा समझते हैं। डिजिटल दुनिया में तो वैश्विक स्तर पर सौ से भी कम भाषाओं का उपयोग किया जाता है। वैश्वीकरण के इस दौर में बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए विदेशी भाषा सीखने की होड़ मातृभाषाओं के लुप्त होने के पीछे एक प्रमुख कारण माना जाता है। लुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत में 'लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण' योजना भी चलाई जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने तथा 'लुप्तप्राय भाषाओं के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में केन्द्र की स्थापना' योजना के तहत कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहयोग करता है।

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषाओं के विकास पर काफी ध्यान दिया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि जहां तक संभव हो, कम से कम पांचवीं कक्षा तक तो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार भी शिक्षा का माध्यम, जहां तक व्यावहारिक हो, बच्चे की मातृभाषा ही होनी चाहिए।

दरअसल, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने से यह छात्रों को उनकी पसंद के विषय तथा भाषा को सशक्त बनाने में मददगार साबित होगा और यह भारत में बहुभाषी समाज के निर्माण, नई भाषाओं को सीखने की क्षमता इत्यादि में भी मदद करेगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा के लिए संविधान के अनुच्छेद 350ए में स्पष्ट है कि देश के प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकारी का प्रयास होगा कि वह भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। बहरहाल, हालांकि आज भारत सहित कई बड़े देशों में भाषा को सरल एवं सुगम बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं तैयार की जा रही हैं और छात्रों को विभिन्न भाषाओं की जानकारी मिल सके, इस उद्देश्य से कई विश्वविद्यालयों में भाषा को लेकर नए कोर्स भी तैयार किए जा रहे हैं लेकिन भाषाओं के संरक्षण के लिए गंभीर वैश्विक प्रयासों की सख्त आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

हरियाणा में एचआईवी: पहचान मजबूत, रोकथाम अभी अधूरी

वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा सरकार द्वारा 12.4 लाख से अधिक लोगों की एचआईवी जांच और 5877 पॉजिटिव मामलों की पहचान- यह तथ्य पहली दृष्टि में सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की सक्रियता, प्रशासनिक इच्छाशक्ति और नीति-स्तरीय गंभीरता का प्रमाण प्रतीत होता है। इतने बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग किसी भी राज्य के लिए न तो सरल होती है और न ही सहज।इसके लिए वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित मानवबल, संस्थागत ढांचा और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है।इस दृष्टि से देखें तो यह उपलब्धि हरियाणा की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता और प्राथमिकताओं को दशार्ती है।

यह पहल इस बात का भी संकेत है कि राज्य ने एचआईवी को अब केवल 'सीमित समुदायों' या 'हाशिये के समूहों' से जोड़कर देखने के पुराने और संकीर्ण नजरिये से आगे बढ़कर एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में स्वीकार किया है लेकिन यही आंकड़े जब गहराई से पढ़े जाते हैं, तो वे एक साथ यह चेतावनी भी देते हैं कि संक्रमण की सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक जड़ें अभी भी मजबूत बनी हुई हैं। सवाल यह नहीं है कि कितने लोगों की जांच हुई, बल्कि यह है कि संक्रमण को जन्म देने वाले कारणों पर कितनी प्रभावी रोक लगी।

राज्य में 104 एकीकृत परामर्श एवं परीक्षण केंद्र और 24 एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) केंद्रों का संचालन इस बात का संकेत देता है कि जांच के बाद मरीजों को इलाज की निरंतर श्रृंखला से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 40,000 से अधिक लोगों का नियमित उपचार यह स्पष्ट करता है कि नीति केवल घोषणाओं और कागजी योजनाओं तक सीमित नहीं है। एचआईवी जैसे दीर्घकालिक और आजीवन प्रबंधन की मांग करने वाले रोग में इलाज की निरंतरता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी प्रारंभिक पहचान। इस मोर्चे पर हरियाणा की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है, जो कई अन्य राज्यों के लिए एक सीख भी हो सकती है।

इस अभियान का सबसे सकारात्मक और दूरगामी प्रभाव गर्भवती महिलाओं की बड़े पैमाने पर जांच में दिखाई देता है। 5.65 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग और 613 पॉजिटिव मामलों की पहचान यह दशार्ती है कि मां से बच्चे में संक्रमण रोकने को गंभीरता से प्राथमिकता दी जा रही है। चिकित्सा विज्ञान यह स्पष्ट कर चुका है कि यदि समय रहते एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला को उपचार और परामर्श मिल जाए तो नवजात को संक्रमण से लगभग पूरी तरह बचाया जा सकता है। यह केवल एक चिकित्सा सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है, क्योंकि एचआईवी-मुक्त शिशु को उस कलंक और भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता, जो आज भी संक्रमित बच्चों के जीवन को सीमित कर देता है।

डॉ. सत्यवान सौरभ (हि.स)

दिसंबर 2021 से लागू 2250 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता योजना, जिसके तहत अब तक 54.3 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, यह संकेत देती है कि राज्य सरकार बीमारी को केवल चिकित्सा समस्या के रूप में नहीं देख रही। एचआईवी से प्रभावित व्यक्ति अक्सर रोजगार, सामाजिक स्वीकार्यता और आर्थिक स्थिरता- तीनों से वंचित हो जाता है। बीमारी के साथ जुड़ा सामाजिक भय और भेदभाव उसकी आजीविका के अवसरों को भी सीमित कर देता है। ऐसे में यह वित्तीय सहायता इलाज के साथ जीवन की बुनियादी गरिमा बनाए रखने का एक प्रयास है। भले ही मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में यह राशि अपर्याप्त प्रतीत हो।

फिर भी, कुल जांच के मुकाबले 0.47 प्रतिशत की पॉजिटिविटी दर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से यह मानते आए हैं कि एचआईवी के मामले अक्सर वास्तविक संख्या से कम रिपोर्ट होते हैं। सामाजिक कलंक, भय, गोपनीयता को लेकर आशंका और जानकारी की कमी के कारण बड़ी संख्या में लोग स्वैच्छिक जांच से बचते हैं। ऐसे में सामने आए 5877 मामले संभवतः समस्या की पूरी तस्वीर नहीं, बल्कि उसका एक सीमित हिस्सा मात्र हैं। यह दर राज्य में मौजूद उन सामाजिक कारकों की ओर भी संकेत करती है, जो संक्रमण को बढ़ावा देते हैं- जैसे नशीली दवाओं का बढ़ता दुरुपयोग, असुरक्षित यौन व्यवहार, तेज शहरीकरण और प्रवासी श्रमिकों की अस्थिर जीवन-स्थितियां।

यौनकर्मी, ट्रक चालक, निर्माण श्रमिक और नशीली दवाओं के आदी लोग आज भी संक्रमण की श्रृंखला में सबसे अधिक जोखिम में हैं। इनके लिए चलाई जा रही लक्षित परियोजनाएं और ओपिओइड प्रतिस्थापन केंद्र निःस्संदेह सही दिशा में कदम हैं, लेकिन इनकी पहुंच और प्रभाव अभी भी सीमित दिखाई देता है। नशे की समस्या को केवल उपचार या दवा वितरण तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा। जब तक इसे सामाजिक पुनर्वास, रोजगार के अवसरों और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन से नहीं जोड़ा जाता, तब तक एचआईवी नियंत्रण अधूरा ही रहेगा।

इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ी और सबसे अदृश्य बाधा आज भी कलंक है। लोग बीमारी से कम और समाज की प्रतिक्रिया से अधिक डरते हैं। एचआईवी आज भी नैतिकता, चरित्र और 'गलती' के साथ जोड़कर देखा जाता है, जबकि यह एक चिकित्सकीय स्थिति है। यही सोच लोगों को जांच से दूर रखती है, इलाज में देरी कराती है और संक्रमण को चुपचाप फैलने का अवसर देती है। रेड रिबन क्लब, रेडियो जिंगल और सोशल मीडिया अभियानों से जागरूकता बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं तक यह संदेश अभी भी पूरी मजबूती से नहीं पहुंच पाया है।

एचआईवी नियंत्रण को केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मानना एक बड़ी रणनीतिक भूल होगी। सुरक्षित प्रवास, श्रमिक कल्याण, नशामुक्ति, लैंगिक समानता और वैज्ञानिक यौन शिक्षा, ये सभी विषय सीधे इस समस्या से जुड़े हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर जांच, परामर्श और इलाज की व्यवस्था न केवल संक्रमण को नियंत्रित कर सकती है, बल्कि उनकी उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ा सकती है। परिवहन, श्रम, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों के साथ समन्वय के बिना कोई भी प्रयास स्थायी परिणाम नहीं दे सकता।

भारत के 'एड्स मुक्त' लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका निर्णायक है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा तय की गई रणनीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में हरियाणा जैसे संसाधन-संपन्न और प्रशासनिक रूप से सक्षम राज्य अगर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो वे केवल आंकड़ों में सफलता हासिल नहीं करेंगे, बल्कि नीति-मॉडल के रूप में भी उभर सकते हैं।

अंततः, हरियाणा का एचआईवी जांच अभियान निःस्संदेह एक बड़ी उपलब्धि है। इसने यह साबित किया है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप संभव हैं, लेकिन यह सफलता तभी पूर्ण मानी जाएगी जब इसके साथ जुड़ी चेतावनियों को गंभीरता से सुना जाए। यदि राज्य कलंक तोड़ने, रोकथाम को इलाज जितनी प्राथमिकता देने और संक्रमण के सामाजिक कारणों पर ईमानदारी से काम करने में सफल होता है, तो आज के आंकड़े कल की सफलता की कहानी बनेंगे। अन्यथा, यही आंकड़े भविष्य के एक बड़े और गहरे संकट का शुरूआती संकेत बनकर रह जाएंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज कार्यस्थल पर कुछ गलत संगत या भ्रमित करने वाले लोगों के कारण परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए संयमित और विनम्र व्यवहार बनाए रखना आवश्यक होगा। शारीरिक रूप से कमर के निचले हिस्से में असहजता महसूस हो सकती है, इसलिए आराम का ध्यान रखें। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं और आपकी सोच तथा दृष्टिकोण दूसरों को प्रभावित करेंगे। परिवार में बड़े भाई-बहनों के जीवन में खुशखबरी या सुधार देखने को मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम तेजी से पूरे होंगे और अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: कार्यालय में अधीनस्थों पर अत्यधिक भरोसा करने से बचना बेहतर रहेगा। खान-पान का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। व्यापार में सहयोगियों की मदद से कार्य आगे बढ़ेंगे और आर्थिक दबाव कम हो सकता है। निर्माण या विकास से जुड़े कार्यों में प्रगति दिखाई देगी। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: आज विशेष रूप से महिलाओं को सराहना और सम्मान मिल सकता है। विदेश से जुड़े अवसर बन सकते हैं, इसलिए नए प्रस्तावों पर ध्यान दें। पिता या गुरुजनों का मार्गदर्शन सफलता की दिशा में सहायक होगा। अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा और भाग्य का साथ बना रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: कार्यक्षेत्र से जुड़ा दबाव मानसिक तनाव दे सकता है और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने में कठिनाई हो सकती है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक संयम रखें। त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचें। बावजूद इसके, आपकी छवि और व्यक्तित्व से लोग प्रभावित रहेंगे। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: मित्रों से मतभेद दूर करने का उपयुक्त समय है। सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। कम प्रयास में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पैतृक व्यवसाय में विस्तार के संकेत हैं और परिवार में शुभ आयोजन का वातावरण बन सकता है। *(सिटी दर्पण)*

तुला: छिपे विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। परिवार में आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है, इसलिए स्पष्ट संवाद बनाए रखें। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी से मतभेद हो सकता है। आयात-निर्यात से जुड़े कार्यों में वृद्धि होगी, लेकिन अधिकारियों को संतुष्ट रखने के लिए सावधानी बरतें। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: शिक्षा या प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में अच्छे परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। विदेश व्यापार या आयात-निर्यात से लाभ मिलने के संकेत हैं। अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास सफल रहेगा। नए समझौते करते समय सतर्क रहें। प्रेम संबंधों में खुलकर संवाद करने का अवसर मिलेगा। *(सिटी दर्पण)*

धनु: वैवाहिक जीवन में मधुरता और रोमांटिक माहौल बना रहेगा। ऑनलाइन लेन-देन करते समय सतर्क रहें। आध्यात्मिक चर्चाओं या ज्ञानवर्धक विषयों में रुचि बढ़ सकती है। छोटे उद्योगों या होटल-रेस्तरां से जुड़े कारोबारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। *(सिटी दर्पण)*

मकर: आज आय के नए साधन विकसित करने का अवसर मिलेगा। व्यापार में अच्छे ग्राहकों के कारण स्थिरता बनी रहेगी। बुजुर्गों के लिए पुराने अनुभवों को याद कर आनंद लेने का समय है। वैवाहिक जीवन संतोषजनक रहेगा और प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को परिवार का सहयोग मिल सकता है। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: व्यवसाय को संतुलित रखने के लिए ऋण लेने की स्थिति बन सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत रहेगी। मधुमेह से ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तनावपूर्ण परिस्थितियों से दूरी बनाए रखें। बेरोजगार लोगों में नौकरी को लेकर चिंता बनी रह सकती है। *(सिटी दर्पण)*

मीन: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल रहेगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। कला या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी है। कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

पृथ्वी की निचली कक्षा में अदृश्य की निगरानी

कृतिका शर्मा(हि.स)

पृथ्वी की निचली कक्षा के शांत, निर्वात-भरे विस्तार में छुपा-छुपी का एक उच्च-दांव वाला खेल चल रहा है। आज अरबों डॉलर के उपग्रहों से लेकर अंतरिक्ष मलबे के नुकीले टुकड़ों तक 24,000 से अधिक वस्तुएं शून्य में तेजी से दौड़ रही हैं। पांच वर्षों के भीतर यह संख्या 70,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। देशों के लिए चुनौती अब केवल भीड़ और टक्कर के जोखिम का प्रबंधन करना नहीं रह गई है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनकी संपत्तियां शत्रुतापूर्ण या दुष्ट तत्वों द्वारा जानबूझकर किए जाने वाले हस्तक्षेप से सुरक्षित रहें।

विवादित वातावरण में केवल रडार पर किसी वस्तु को देखना ही नहीं, बल्कि उसके इरादे को समझना भी आवश्यक है। जब कोई उपग्रह नहीं चाहता कि उसे पाया जाए, या जब वह कोई अप्रत्याशित युद्धाभ्यास करता है, तो पारंपरिक जमीनी-आधारित ट्रैकिंग अक्सर विफल हो जाती है। इस अंतर को पाटने के लिए, अमेरिका के रक्षा विभाग की डिफेंस इनोवेशन यूनिट ने यूएस स्पेस फोर्सेज-इंडो-पैसिफिक और स्पेस डोमेन अवेयरनेस टूल्स, एप्लिकेशन्स एंड प्रोसेसिंग लैब के साथ साझेदारी में तथा भारत की इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के समर्थन से, 'ड्यूल होराइजन्स: यूएस-इंडिया सैटेलाइट ट्रैकिंग चैलेंज' शुरू किया, जो अंतरिक्ष-डोमेन जागरूकता की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक द्विपक्षीय प्रयास है।

समस्या को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि बिना कैमरों या जीपीएस के एक रेगिस्तान में एक स्वचालित वाहन चलाया जा रहा है। उसके स्थान की पुष्टि करने का

एकमात्र तरीका यह है कि उसके किसी निश्चित, स्थिर चेकपॉइंट से गुजरने का इंतजार किया जाए। अब इसमें 17,000 मील प्रति घंटे की गति से चल रहे हजारों अन्य वाहनों को जोड़ दीजिए। यदि कोई वाहन अचानक मुड़ जाता है, तो वह प्रभावी रूप से प्रणाली के लिए 'खो' जाता है।

यही पारंपरिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता की वास्तविकता है। मानक तरीके पूर्वानुमेय कक्षीय गणित पर निर्भर करते हैं। यदि कोई उपग्रह 'स्क्रिप्ट' के अनुसार चलता है तो हमें पता होता है कि वह कहां है, लेकिन आधुनिक विरोधी छुपाव और छलपूर्ण युद्धाभ्यास का उपयोग कर-के गायब हो जाते हैं। जैसे ही कोई उपग्रह अपने अनुमानित मार्ग से विचलित होता है उसे फिर से हासिल करने में घंटे या दिन लग सकते हैं, जिससे महत्वपूर्ण अवसंरचना असुरक्षित हो जाती है।

अमेरिका-भारत 'ड्यूल होराइजन्स' चैलेंज की विजेता दिगंतरा इंडो-पैसिफिक में 'ब्लाइंड स्पॉट्स' को समाप्त करने वाली सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रणाली के साथ अंतरिक्ष सुरक्षा को मजबूत कर रही है। ड्यूल होराइजन्स चैलेंज के विजेताओं में से एक, बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप दिगंतरा के संस्थापक अनिरुद्ध शर्मा एक बड़े भौगोलिक जोखिम की ओर इशारा करते हैं। अमेरिका वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में प्राथमिक सेंसर बनाए रखता है। शर्मा कहते हैं, 'इनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है।' वे यह भी कहते हैं कि दिगंतरा इस क्षेत्र में उपग्रह गतिविधि को ट्रैक करने के लिए अमेरिकी एजेंसियों के साथ काम कर रही है।

दिगंतरा का विजेता समाधान, स्पेक्ट्रे इन ब्लाइंड स्पॉट्स को उजागर करने का लक्ष्य रखता है। जमीन से आकाश की ओर दृष्टिकोण बदलकर, स्पेक्ट्रे कक्षा से अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करता है। शर्मा बताते हैं, 'परंपरागत रूप से प्रणालियां जमीनी-आधारित होती हैं। हमारा समाधान कक्षा से ट्रैक करता है, जिसका अर्थ है कि हम वायुमंडलीय विकृतियों और रेंज से जुड़ी समस्याओं को पार कर जाते हैं।' अंतरिक्ष में एक गतिशील प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, दिगंतरा संपत्तियों पर एक सतत 'दृश्य' प्राप्त करता है, जिससे अधिक बार डेटा संग्रह और कहीं अधिक सटीकता संभव होती है।

जहां अधिकांश व्यावसायिक कंपनियां आकाश में मौजूद वस्तुओं की जानकारी के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग के 'कैटलॉग' पर निर्भर करती हैं, वहीं दिगंतरा अपना स्वयं का स्वतंत्र भंडार बना रही है। इसके सेंसर सॉफ़्टबॉल जितनी छोटी वस्तुओं का भी पता लगा सकते हैं, जो खुफि या जानकारी की एक विशिष्ट परत प्रदान करते हैं। इस स्वतंत्रता ने स्टार्ट-अप को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण साझेदार बनाया है।

दिगंतरा वर्तमान में अमेरिका के साथ डेटा-साझाकरण समझौते के तहत काम करती है, जिससे उसकी विशिष्ट ब्लाइंड-स्पॉट डेटा को मौजूदा अमेरिकी सैन्य कैटलॉग के साथ प्रभावी रूप से जोड़ा जाता है। इंटरऑपरेबिलिटी इसकी सफलता का 'प्लग-एंड-प्ले' रहस्य है। स्पेक्ट्रे को मौजूदा मिशन नेटवर्क में निर्बाध रूप से एकीकृत होने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कमांडरों को बिना अपने सॉफ़्टवेयर को नए सिरे से बनाए वास्तविक समय का डेटा मिल सकता है। अब अमेरिका में कार्यालयों और इंडो-पैसिफि क में गहरे संबंधों के साथ, दिगंतरा एक सिस्टम्स इंटीग्रेटर के रूप में स्थापित है।

दिगंतरा की सफलता अमेरिका-भारत समन्वय का एक उदाहरण है। शर्मा कहते हैं, 'हम अमेरिकी बाजार में विस्तार के हिस्से के रूप में अपने अमेरिकी कार्यालय में और निवेश करने की योजना बना रहे हैं। हम एक समर्पित टीम और सुविधा का निर्माण कर रहे हैं, जो सैटेलाइट और पेलोड असेंबली के साथ-साथ मिसाइल रक्षा अनुप्रयोगों पर केंद्रित होगी। हाल ही में अमेरिका आधारित एक कार्यक्रम के लिए हमारे चयन ने हमें यह निवेश करने और इस पहल को शुरू करने का आत्मविश्वास और आधार दिया है।'

2,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने वाले पंजाब के पहले शिक्षा मंत्री बने हरजोत सिंह बैंस

शिक्षा मंत्री ने कहा, भगवंत मान सरकार पठानकोट से लेकर फाजिल्का तक सरकारी स्कूलों की नुहार बदलने के मिशन पर

बच्चों को सही तरीके से न पढ़ाने वाले शिक्षकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: बैंस

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़ / अमृतसर

पंजाब में शिक्षा सुधारों की श्रृंखला में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने राज्य की सरकारी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और इसके सुधार से संबंधित अपनी निरंतर मुहिम के हिस्से के रूप में आज सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, झीता कलां का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरे के दौरान स. बैंस ने बताया कि उन्होंने पद संभालने से अब तक पंजाब भर के 2,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया है, जिसे उन्होंने राज्य के इतिहास में एक नया मानक करार दिया।

शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मैंने पद संभालने से लेकर राज्य भर के 2,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का जमीनी स्तर पर दौरा करके नया रिकॉर्ड कायम किया है।यह पंजाब के इतिहास में पहली बार है जब किसी शिक्षा मंत्री ने शिक्षा प्रणाली की इतने बड़े स्तर पर जमीनी स्तर पर समीक्षा की है।

उन्होंने आगे कहा कि इस मुहिम के तहत मैंने पठानकोट से फाजिल्का, फिरोजपुर से मोहाली तक कोई जिला नहीं छोड़ा है, जो राज्य के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रति मेरे जुनून को दशार्ता है।उन्होंने कहा कि पंजाब में लगभग 20,000 स्कूल हैं, जिनके जमीनी स्तर पर निरीक्षण के लिए मैं एक मिशन पर हूं।

स्टाफ और विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने स्कूल में शिक्षा और प्रबंधन के मानकों की समीक्षा की और 'समर्थ' कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन भी किया, जो प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई-लिखाई से संबंधित समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।

स. बैंस ने पद संभालने के समय सरकारी स्कूल शिक्षा प्रणाली की स्थिति को याद करते हुए कहा कि प्राइमरी स्तर पर बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ने या लिखने में असमर्थ थे।सीखने की खाई को भरने में इस पहल के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करते हुए वे जब ऐसे बच्चों से बात करते हैं, जो अक्षरों की पहचान करने में संघर्ष से लेकर अब शब्दों और वाक्यों को आत्मविश्वास से पढ़ने तक प्रगति कर चुके हैं, तो उन्हें बहुत खुशी और संतुष्टि होती है।

स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि 'समर्थ' कार्यक्रम के माध्यम से हमने ऐसे बच्चों की पहचान करके उन पर काम किया।उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाने वाले शिक्षक शानदार परिणाम दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ऐसी किसी भी लापरवाही के प्रति भगवंत मान सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति की पुष्टि करते हुए शिक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हरजोत बैंस ने इंडिया ए.आई. इम्पैक्ट एक्सपो में पंजाब के स्कूलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संभावनाओं को तलाशा

चंडीगढ़/नई दिल्ली। राज्य की शैक्षिक संरचना के भविष्य को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग का उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज भारत मंडपम, नई दिल्ली में इंडिया ए.आई. इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में शामिल हुआ।यहां उन्होंने राज्य के विशाल स्कूली ढांचे के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित विस्तृत संभावनाओं और शिक्षा के अधिक रचनात्मक परिणामों के लिए समाधान तलाशने हेतु विश्व-स्तरीय तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों और केंद्र सरकार के संस्थानों के साथ लगातार रणनीतिक विचार-विमर्श में भाग लिया। प्रदर्शनी हॉलों के व्यापक दौरे के दौरान, जिसमें उनके साथ स्कूल शिक्षा के सचिव सोनाली गिरि, पी.एस.ई.बी. के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह और डी.जी.एस.ई. अरविंद भी मौजूद थे, शिक्षा मंत्री ने गूगल, डेलॉइट, इंटेल, ओपन एआई, एनवीडिया और डेल सहित प्रमुख विश्व तकनीकी कंपनियों के साथ बातचीत की।उन्होंने पंजाब की शिक्षा प्रणाली में उन्नत एआई तकनीकों को अपनाने पर विशेष ध्यान देते हुए भविष्य की शिक्षा के बारे में विचार-चर्चा की।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की और देश की एआई रणनीति, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तथा गवर्नेंस मॉडलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जो पंजाब के कक्षाओं के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा और ए.आई. पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी कंपनियों, जिनमें वाधवानी एआई, जीएनएएनआई. एआई और बोध एआई शामिल हैं, के साथ विस्तृत विचार-विमर्श भी किया। ये विचार-विमर्श एआई-सक्षम स्कूल शिक्षा एप्लिकेशनों पर केंद्रित थे, जिसमें व्यक्तिगत अनुकूलित शिक्षण (पी.ए.एल.), मूलभूत साक्षरता और गणित शिक्षा (एफएलएन), एआई-सक्षम मूल्यांकन, बहुभाषी शिक्षण उपकरण, शिक्षक सहायता तथा मजबूत शासन और बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए समय-आधारित निगरानी प्रणालियों के विश्लेषण पर चर्चा की गई।

मान सरकार किसानों को बीज से बाजार तक पूरा सहयोग दे रही है: मोहिंदर भगत

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

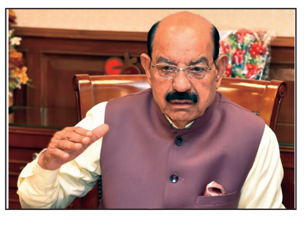

पंजाब के बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने शुक्रवार को कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने और बागवानी को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को बीज से लेकर बाजार तक हर स्तर पर पूर्ण सहयोग उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली बीज सामग्री, तकनीकी सलाह, आधुनिक खेती के तरीके और मजबूत बाजार लिंकेज उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं।

बागवानी मंत्री भगत ने कहा कि सरकार की किसान-पक्षीय नीतियां और हर स्तर पर पूर्ण सहयोग किसानों को पारंपरिक फसलों के चक्र से बाहर अधिक मूल्य वाली बागवानी फसलों की ओर प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि फल, सब्जियां और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलें किसानों के लिए अधिक लाभदायक साबित हो रही हैं। इसके साथ ही पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड चेन, पैकहाउस और प्रोसेसिंग सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके।

मंत्री ने कहा कि फसलों की विविधता समय की आवश्यकता है और इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि मिट्टी की सेहत और भूजल की संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार किसानों की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र को मजबूत करके राज्य को कृषि में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास जारी रहेंगे।

सभी एस.सी. कर्मचारी संगठनों की समस्याएं सुनने के लिए 23 को विशेष बैठक: गढ़ी

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित पंजाब की एस.सी. कर्मचारी संगठनों की समस्याओं तथा संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने में आ रही कठिनाइयों को सुनने के लिए 23 फरवरी 2026 (सोमवार) को एक विशेष बैठक बुलाई गई है। यह बैठक पंजाब भवन, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। बताया गया कि बैठक में राज्य के हर एस.सी. कर्मचारी संगठन की ओर से दो-दो प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रत्येक संगठन की ओर से अपने प्रतिनिधियों संबंधी अधिकृत पत्र, पहचान पत्र या अन्य संबंधित दस्तावेज पंजाब भवन के प्रवेश द्वार पर जमा करवाना अनिवार्य होगा।

पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने उद्योगपति सज्जन जिंदल से की मुलाकात

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

राजपुरा में इस्पात क्षेत्र में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने शुक्रवार मुंबई में प्रमुख उद्योगपति एवं सज्जन जिंदल, चेयरमैन, जेएसडब्ल्यू समूह से महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पंजाब इन्वेस्ट के सीईओ अमित ढाका भी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान सज्जन जिंदल ने राजपुरा में इस्पात क्षेत्र में 1,500 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि खरह समूह पंजाब में अपने विविध व्यवसायिक क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश की संभावनाओं का अन्वेषण करेगा। प्रस्तावित निवेश से राज्य के विनिर्माण आधार को मजबूती मिलेगी, इस्पात मूल्य श्रृंखला गहरी होगी तथा क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे।

जिंदल ने 13 मार्च को प्लाक्षा विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट पंजाब समिट के उद्घाटन सत्र में अपनी उपस्थिति की भी पुष्टि की। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे उद्योग-अनुकूल वातावरण और सक्रिय औद्योगिक पहुँच प्रयासों की सराहना की।

मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब की मजबूत औद्योगिक नींव को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य उत्तरी बाजारों से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी, सशक्त एमएसएमई तंत्र, कुशल मानव संसाधन तथा इस्पात, ऑटो कंपोनेंट्स, वस्त्र, खेल सामान, खाद्य प्रसंस्करण और लाइट इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में विकसित औद्योगिक क्लस्टरों से युक्त है। उन्होंने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुधारों में पंजाब को लगातार 'टॉप अचीवर' के रूप में मिली मान्यता तथा समयबद्ध स्वीकृतियों के लिए प्रगतिशील सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली का भी उल्लेख किया। मंत्री ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार नई, सुदृढ़ एवं भविष्य उन्मुख औद्योगिक नीति को अंतिम रूप देने के उन्नत चरण में है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के विनिर्माण और प्रौद्योगिकी आधारित निवेश को प्रोत्साहित करना है।यह नीति प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रोत्साहन, प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक अवसंरचना, क्षेत्र-विशिष्ट पार्क, त्वरित स्वीकृतियाँ, बेहतर लॉजिस्टिक्स दक्षता तथा रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए मजबूत नीति समर्थन पर केंद्रित होगी। मूल्य संवर्धित विनिर्माण को बढ़ावा देने, निर्यात में वृद्धि तथा पंजाब के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

पंजाब सरकार की सक्रिय एवं उद्योग-अनुकूल नीतियों की सराहना करते हुए जिंदल ने राज्य में नए निवेश आकर्षित करने हेतु मंत्री संजीव अरोड़ा के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की तथा स्थिर एवं अनुकूल कारोबारी वातावरण सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया। उन्होंने रक्षा निर्माण, ऑटोमोबाइल क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में संभावनाएँ तलाशने में गहरी रुचि व्यक्त की। मंत्री संजीव अरोड़ा ने उद्योगों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रस्तावित खरह परियोजनाओं के लिए हर संभव सहयोग, मार्गदर्शन और त्वरित स्वीकृतियों का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, बेहतर लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और उत्तरदायी प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बैठक प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 से पूर्व समावेशी विकास, औद्योगिक विविधीकरण और रोजगार सृजन के विजन के अनुरूप, पंजाब को भारत के सबसे पसंदीदा और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्यों में स्थापित करने के सतत प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है मातृभाषा, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग: राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू

पंजाब राज्य सूचना आयोग ने पंजाबी भाषा की महत्ता को दशार्ता साहित्यिक ब्रोशर जारी किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस-2026, जो हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है, की महत्ता को मान्यता देते हुए और मातृभाषा पंजाबी को और अधिक प्रफुल्लित करने के लिए पंजाब के मुख्य सूचना आयुक्त इंद्रपाल सिंह धन्ना द्वारा राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू, वरिंदरजीत सिंह बिलिंग, डॉ. भूपिंदर सिंह बाथ, संदीप सिंह धालीवाल, पूजा गुप्ता तथा डी.के. तिवारी (आई.ए.एस.), अतिरिक्त मुख्य सचिव पंजाब सरकार की उपस्थिति में, आज यहां पंजाबी मातृभाषा को दशार्ता एक साहित्यिक ब्रोशर जारी किया गया। यह साहित्यिक ब्रोशर राज्य सूचना आयुक्त, पंजाब हरप्रीत संधू द्वारा लिखा गया है, जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस-2026 के थीम ''बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज'' को उजागर करते हुए समाज में मातृभाषा ''पंजाबी'' को मान्यता देने और उसकी शान बहाल करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

पंजाब सूचना आयोग मुख्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान पंजाब राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू ने बताया कि उन्होंने यह पिक्टोरियल (तस्वीरों सहित) ब्रोशर नेल्सन मंडेला द्वारा कही गई प्रसिद्ध उक्ति से प्रेरित होकर तैयार किया है, ''यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है, तो शब्द उसके दिमाग में जाते हैं, लेकिन यदि आप उससे उसकी मातृभाषा में बात करते हैं, तो वे उसके दिल तक पहुंचते हैं।'' ताकि मातृभाषा पंजाबी की शानदार विरासत को और अधिक प्रफुल्लित किया जा सके।राज्य सूचना आयुक्त पंजाब ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस-2026 का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़कर मातृभाषा को अपनाने, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक करना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पंजाब, डी.के. तिवारी ने हरप्रीत संधू द्वारा तैयार साहित्यिक ब्रोशर की प्रशंसा की और इसे पंजाबी भाषा के प्रचार के लिए सार्थक प्रयास बताया।

इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत संधू, वरिंदरजीत सिंह बिलिंग, डॉ. भूपिंदर सिंह बाथ, संदीप सिंह धालीवाल तथा पूजा गुप्ता ने भी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की महत्ता पर अपने विचार साझा किए, क्योंकि मातृभाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान और विरासत की आत्मा है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमारे इतिहास तथा रीति-रिवाजों को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाती है। राज्य सूचना आयुक्तों ने कहा कि अपनी मातृभाषा को संभालकर और उत्साहित करके, हम न केवल अपनी विरासत का सम्मान करते हैं बल्कि मानवता की विविधता और एकता में भी योगदान डालते हैं।

हरमीत सिंह कालका ने राज्य सभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी को जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका ने राज्यसभा सदस्य श्री विक्रमजीत सिंह साहनी को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में सरदार कालका ने कहा कि श्री विक्रमजीत सिंह साहनी ने सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय एकता और मानवता की भलाई के लिए अमूल्य योगदान दिया है। उनकी निस्वार्थ सेवा भावना और सक्रिय सामाजिक भूमिका समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उन्होंने अरदास की कि वाहेगुरु जी श्री साहनी को उत्तम स्वास्थ्य, दीघार्यु और अटूट साहस प्रदान करें, ताकि वे आगे भी देश और सिख समुदाय की निरंतर सेवा करते रहें। सरदार कालका ने कहा कि हमें आशा है कि श्री विक्रमजीत सिंह साहनी अपनी दूरदर्शी सोच और समर्पित नेतृत्व के माध्यम से सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर नए मानदंड स्थापित करते रहेंगे।

मोहाली कांग्रेस ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ डीसी मोहाली को सौंपा ज्ञापन

यह व्यापार समझौता पंजाब के किसानों की कमर तोड़ देगा: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि प्रस्तावित भारतझ्रअमेरिका व्यापार समझौता पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों की आजीविका के लिए गंभीर खतरा है।इस संबंध में एक ज्ञापन जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा, बलबीर सिंह सिद्धू और मोहाली के अन्य कांग्रेस कार्यकताओं द्वारा डिप्टी कमिश्नर, मोहाली को सौंपा गया। बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि सीमावर्ती और मुख्यतः कृषि आधारित राज्य होने के कारण पंजाब पर इस समझौते का सबसे अधिक नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि सस्ती विदेशी कृषि उपज को भारतीय बाजारों में प्रवेश मिला, तो सीमित भूमि जोत पर खेती करने वाले पंजाब के छोटे और सीमांत किसान, भारी सरकारी सब्सिडी और अत्याधुनिक तकनीक से लैस बड़े अमेरिकी किसानों से कभी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, जिससे किसान गहरे संकट में चले जाएंगे।

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कमजोर होने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और कम होंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ने से नशे की समस्या और गंभीर होगी, जिससे राज्य में सामाजिक अस्थिरता बढ़ेगी। रणनीतिक चिंताओं का उल्लेख करते हुए बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में आर्थिक अस्थिरता और युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी का फायदा देश-विरोधी ताकतें उठा सकती हैं।उन्होंने कहा कि मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर युवा ही राज्य की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की असली ढाल हैं।देश के पूर्व नेतृत्व का हवाला देते हुए बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. मनमोहन सिंह ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की और भारत में खाद्य संकट के दौर में भी कृषि बाजारों को विदेशी उत्पादों के लिए नहीं खोला।

सामाजिक सुरक्षा विभाग के 8 नव-नियुक्त क्लर्कों को डॉ. बलजीत कौर ने सौंपे नियुक्ति पत्र

नव-नियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी और लोक-सेवा की भावना से काम करने की अपील

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब सिविल सचिवालय में अपने कार्यालय कक्ष में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए गए 8 नव-नियुक्त क्लर्कों को नियुक्ति पत्र सौंपे।इस अवसर पर मंत्री ने नव-नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्हें लोक-हित में अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और तनदेही से निभाने की अपील की।

मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हर कर्मचारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कर्मचारियों का समर्पण भाव से काम करना बहुत जरूरी है।डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा सभी नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित तरीके से की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्म-निर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि अब तक पंजाब सरकार द्वारा लगभग 64,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं, जो युवा रोजगार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी विभाग की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनके द्वारा ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया गया काम ही सरकारी नीतियों और योजनाओं को लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचाता है।इसलिए हर कर्मचारी का योगदान राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पारदर्शी, लोक-हितैषी और युवा-केंद्रित नीतियों के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिससे एक तरफ परिवारों को आर्थिक सहारा मिल रहा है और दूसरी तरफ सरकारी विभागों की कार्यक्षमता और मजबूत हो रही है।

नियुक्ति

अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम

चौंदा ने पंजाब एससी भूमि विकास और वित्त निगम के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलजीत कौर और तरुणप्रीत सिंह सौंद की मौजूदगी में नव-नियुक्त चेयरमैन ने पदभार ग्रहण किया

पंजाब अनुसूचित जातियां और भूमि विकास और वित्त निगम के नव-नियुक्त चेयरमैन बलजिंदर सिंह चौंदा ने आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर तथा ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद की मौजूदगी में सरकारी तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया।इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रियों ने नव-नियुक्त चेयरमैन को बधाई दी।

इस मौके पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. बलजीत कौर और ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों और दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एस.सी. वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं, आसान ऋण सुविधाएं और ऋण माफी जैसे ऐतिहासिक फैसले यह साबित करते हैं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य हर योग्य लाभार्थी तक सरकारी सहायता पहुंचाना है।

उन्होंने आगे कहा कि नव-नियुक्त चेयरमैन के नेतृत्व में निगम एस.सी. वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाएगा। कार्यभार संभालने के बाद चेयरमैन बलजिंदर सिंह चौंदा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर, ग्रामीण विकास मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद का उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद किया।चेयरमैन ने कहा कि अनुसूचित जातियों के वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना पंजाब सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर ठोस और परिणाम-केंद्रित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एस.सी. वर्ग से संबंधित पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरल, पारदर्शी और आसान प्रक्रिया के माध्यम से ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा एस.सी. वर्ग के 4,727 परिवारों का ऋण माफ किया जा चुका है, जो सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील कदम है। इसके साथ ही एस.सी. वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गांवों और शहरी क्षेत्रों में विशेष जागरूकता शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि हर योग्य लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर पंजाब सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की निदेशक विम्मी भुल्लर आई.ए.एस., अन्य विशेष व्यक्तित्व और नव-नियुक्त चेयरमैन के पारिवारिक सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे।

एआई समिट में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लिया हिरासत में

कार्यकर्ताओं ने अपनी टी-शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रहे 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकताओं ने शुक्रवार को यहां केन्द्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यकताओं ने अपनी टी-शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। फिलहाल, कांग्रेस के कार्यकताओं को हिरासत में ले लिया गया है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महला ने कहा, यह आज दोपहर करीब 12:30 बजे की घटना है। इन लोगों ने क्यूआर कोड के जरिए आवेदन किया और फिर ये लोग अंदर आए। उन्होंने स्वेटर और जैकेट पहनी हुई थी और बाद में उन लोगों ने हॉल नंबर 5 के लॉबी एरिया में स्वेटर और जैकेट उतारकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा कि हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य लोगों की पहचान की जा रही है।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष बोले- विरोध एआई समिट के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में किए विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी ले ली है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में शुक्रवार को प्रदर्शनी हॉल के पास भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो वाली टी-शर्ट लहराकर नारेबाजी की थी। युवा कांग्रेस ने इस पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिम्मेदारी ली और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब का बयान भी जारी किया। उदय भानु चिब ने कहा कि यह विरोध एआई समिट के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन समझौतों के खिलाफ था जिन्हें वे भारत के हितों के साथ समझौता मानते हैं। उन्होंने कहा कि देश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका के साथ हो रहे व्यापार समझौते से किसानों और आम जनता को नुकसान होगा और इसका फायदा केवल अमेरिका को मिलेगा। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना उनका अधिकार है और वे युवाओं की आवाज बुलंद करते रहेंगे। चिब ने कहा कि जब किसानों और युवाओं के हितों का सौदा किया जा रहा हो, तब चुप रहना संभव नहीं है। अगर सरकार सोशल मीडिया पर आईटी नियमों के जरिए विरोधी आवाजों को दबाती है और सड़कों पर प्रदर्शन करने से रोकती है, तो उनके पास विरोध दर्ज कराने का यही तरीका बचता है।

एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की केंद्रीय मंत्रियों ने की आलोचना

नई दिल्ली। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की कड़ी आलोचना हो रही है। केंद्रीय मंत्रियों ने घटना को शर्मनाक बताते हुए इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिह ने एक्स पोस्ट पर कहा कि यूथ कांग्रेस का अनुचित व्यवहार न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास भी है। वे कांग्रेस के इस कृत्य की भर्त्सना करते हैं। उन्होंने कहा, जब भी भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ता है, कांग्रेस राष्ट्रहित के साथ खड़े होने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने को प्राथमिकता देती दिखाई देती है। दलगत राजनीति को देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से ऊपर रखना अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता भलीभांति समझती है कि कौन भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में जुटा है और कौन बार-बार भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने घटना को कांग्रेस के अहंकार और हताशा का जीता-जागता उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को निशाना बनाने के लिए भारत को अपमानित करना ही राहुल गांधी और विपक्ष का तरीका है। वे हालिया व्यापार समझौतों के बारे में झूठ फैलाकर भारत के विकास को रोकना चाहते हैं। वहीं उनके कार्यकर्ता प्रतिष्ठित एआई शिखर सम्मेलन में बिना शर्ट पहने मार्च कर रहे हैं, ताकि 14 करोड़ भारतीयों को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा कर सकें। यह विघटनकारी रणनीति केवल भारत के लिए आपकी और आपकी पार्टी की दूरदृष्टि की कमी को उजागर करती है।

अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मानहानि केस में राहुल गांधी ने दर्ज कराया अपना बयान

एजेंसी (हि.स.)
सुलतानपुर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में मानहानि केस का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को स्थानीय एमपी /एमएलए कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। राहुल गांधी ने इस केस को सस्ती लोकप्रियता का मामला बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए 10:50 बजे सीधे स्था कोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी ने स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए मुझ पर साजिशन केस किया गया है। इस दौरान कोर्ट में वे 20 मिनट रुके। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 मार्च की तिथि नियत की है। राहुल गांधी आज ही वापस लखनऊ जाएंगे। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। दरअसल, कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में पिछले पांच वर्ष से अदालती कार्यवाही चल रही है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार गवाह राम चंद्र दुबे को 6 जनवरी को पेश किया गया था। उनसे डिफेन्स काउंसिल ने जिरह की कार्रवाई पूरी की थी। अब फाइल 313 में कोर्ट ने आज के लिए नियत की थी।

इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़ी प्रबंध किये गए थे। कोर्ट परिसर में एडीएम प्रशाशन गौरव शुक्ला और एएसपी अखंड प्रताप सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे।

शिवाजी जयंती के बाद बागलकोट में फिर पथराव पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 8 आरोपी गिरफ्तार

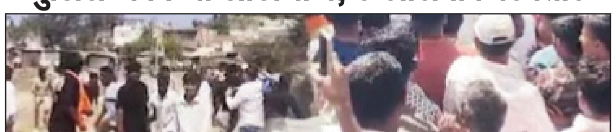

एजेंसी (हि.स.)
बागलकोट

कर्नाटक के बागलकोट शहर में शिवाजी जयंती के अवसर पर निकाली गई झांकी और शोभायात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद हालात सामान्य होने लगे थे, लेकिन शुक्रवार को किल्ला ओणी क्षेत्र में एक बार फिर पथराव की घटना सामने आई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

बताया जा रहा है कि गुरुवार रात की घटना के विरोध में हिंदू संगठनों के नेताओं की शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के बाद कार्यकर्ता बाजार बंद कराने के लिए निकले। इसी दौरान जब वे सब्जी मंडी की ओर बढ़ रहे थे, किल्ला ओणी इलाके में फिर से पत्थर फेंके गए। पत्थर सब्जी विक्रेताओं के पास आकर गिरे, जिससे अफरा-तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर हालात पर काबू पाया गया। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। दरअसल, गुरुवार रात शिवाजी जयंती की शोभायात्रा जब पंका मस्जिद के पास पहुंची थी, तभी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर और चप्पल फेंके जाने की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में एहतियातन निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बागलकोट में हुआ पथराव समाज की शांति और सौहार्द के लिए घातक है।

एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और ब्राजील के बीच कृषि सहयोग पर बनी सहमति

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के दौरान भारत और ब्राजील के कृषि मंत्रियों के बीच कृषि व्यापार और तकनीकी साझाकरण को लेकर व्यापक चर्चा हुई।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिहं चौहान ने शुक्रवार को एक्स पर कहा कि आज कृषि भवन में ब्राजील के कृषि मंत्री और उनकी टीम के साथ कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच आसान बनाने, प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत विशेष रूप से अपने अनार, लहसुन, अंगूर और किशमिश को ब्राजील के बाजारों में निर्यात करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है।

उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और ब्राजील की प्रसिद्ध संस्था ब्राजील की कृषि अनुसंधान निगम (एम्ब्रापा) के बीच सहयोग पर सहमति बनी है। दोनों संस्थाएं मिलकर प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देंगी, जिसके लिए जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत में जारी दलहन और तिलहन मिशन को मजबूती देने के लिए 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया गया। ब्राजील ने एकीकृत कृषि प्रणालियों पर भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई है।

कृषि में एआई का बढ़ेगा उपयोग, स्वास्थ्य और आईटी सेक्टर में भी नई संभावनाएं : मोहन यादव

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और गेहूं, धान और सोयाबीन उत्पादन में देश में अग्रणी है। किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, फसलों में होने वाली बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और सही दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी एआई मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के एक सत्र के दौरान कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एआई का उपयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे बीमारियों की समय पर पहचान और सही इलाज संभव होगा। राज्य सरकार आने वाले समय में कई कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगी और उनके निवेश का लाभ लेगी। बड़े और छोटे शहरों में आईटी पार्क को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार एआई स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें सरकार के साथ काम करने के अवसर दिए जाएंगे। शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भी एआई की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में कई कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए गए हैं और निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। मोहन यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई के उपयोग से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग के साथ-साथ ऊर्जा बचत के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खुलेंगी और मध्य प्रदेश भविष्य में इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका निभाएगा। समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने गूगल के अधिकारियों से भी मुलाकात की और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। एआई के साथ जुड़कर दुनिया के साथ कदम मिलाने का यह अच्छा अवसर है।

संक्षिप्त-समाचार

बिटकॉइन घोटाला मामले में राज कुंद्रा को मिली जमानत

मुंबई। बिटकॉइन घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए मुंबई की विशेष पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) अदालत ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिटकॉइन घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में ईडी ने दुबई के कारोबारी राजेश सतीजा और राज कुंद्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी आरोप पत्र को संज्ञान लेते हुए अदालत ने राज कुंद्रा और दुबई के कारोबारी राजेश सतीजा को समन जारी किया था और दोनों को 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था। लेकिन राज कुंद्रा तय समय पर पेश नहीं हो पाए थे। आज इस मामले की हो रही सुनवाई के दौरान राज कुंद्रा अपने वकील प्रशांत पाटिल के साथ अदालत में पेश हुए थे। इसके बाद राज कुंद्रा के वकील ने आज दोपहर 3 बजे राज कुंद्रा की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। इसके बाद राज कुंद्रा के वकील और सरकारी वकील ने अदालत में अपना पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राज कुंद्रा को जमानत दे दी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद रिकी एंड्रयू जे. सिंगकों के निधन पर जताया शोक

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिलॉन्ग से लोकसभा सांसद डॉ. रिकी एंड्रयू जे. सिंगकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉ. सिंगकों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने मेघालय के विकास और जनता के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। राष्ट्रपति ने दिवंगत सांसद के परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. सिंगकों को मेघालय की जनता की सेवा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उल्लेखनीय है कि शिलॉन्ग से लोकसभा सांसद रिकी एंड्रयू जे सिंगकों का गुरुवार शाम निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे शिलॉन्ग में एक दोस्ताना फुटसल सत्र के दौरान खेलते समय अचानक बेहोश होकर गिर पड़े।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 26 फरवरी को जमशेदपुर दौरे पर आएंगी, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां

पूर्वी सिंहभूम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 26 फरवरी को जमशेदपुर के प्रस्तावित दौरे पर रहेंगी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति कदमा स्थित श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केन्द्र ट्रस्ट के भूमि पूजन समारोह में भाग लेंगी। इसके बाद उनका मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना भी प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा, प्रोटोकॉल और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए अपर पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) मनोज कौशिक और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार ने उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा घेरा, यातायात प्रबंधन, अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, आपात चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति, स्वच्छता और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए समय पर तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है, ताकि राष्ट्रपति का दौरा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे नितिन नवीन

गांधीनगर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर शुक्रवार को अहमदाबाद पहुंचे। सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी सहित भाजपा नेताओं और कार्यकताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने कहा कि 21वीं सदी में भारत विकास और विरासत के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यकताओं के परिश्रम से गुजरात विकसित गुजरात की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज राज्य देश ही नहीं, बल्कि विश्व को भी दिशा दे रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जहां बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी अपनी क्षमता के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उन्होंने पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस बताते हुए सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय की सराहना की। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने कहा कि संगठन भाजपा की आत्मा है और कार्यकर्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने नितिन नवीन की यात्रा को सभी कार्यकताओं के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और पूरे उत्साह के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया।

हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 311 अंक उछला, निफ्टी 25,550 के पार

नई दिल्ली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। ह्यपैक्स सिलिकाह्न में भारत की भागीदारी की खबरों से शेयर बाजार में तेजी लौटी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचें (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 316.57 अंक यानी 0.38 फीसदी उछलकर 82,814.71 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 633.94 अंक बढ़कर 83,132.08 अंक तक पहुंच गया था। सेंसेक्स 317 अंक की बढ़त के साथ, जबकि निफ्टी 25,550 के पार बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सेंचज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला निफ्टी 116.90 अंक यानी 0.46 फीसदी बढ़कर 25,571.25 पर बंद हुआ।

मणिपुर में चार उग्रवादी गिरफ्तार हथियार एवं गोला-बारूद बरामद

एजेंसी (हि.स.)
इंफाल

मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों से चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार एवं गोला-बारूद भी बरामद किया गया है।

मणिपुर पुलिस मुख्यालय के अनुसार गुरुवार को सुरक्षा बलों ने विभिन्न स्थानों से आरपीएफ/पीएलए के दो सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक की पहचान थौनाजोम प्रेमपत्र सिंह उर्फ लुवांग उर्फ प्रेम (31) के रूप में की गयी। उसे इंफाल वेस्ट जिले के सिंगजामेई थानांतर्गत सिंगजामेई चिंगा मुखा से गिरफ्तार किया गया। दूसरे की शिनाख्त थारोइजम टोनी सिंह (32) के रूप में हुई है। उसे इंफाल ईस्ट जिले के पोरोम्पत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से एक 9 मिमी पिस्तौल मैगजीन सहित, चार राउंड 9 मिमी जिंदा कारतूस, एक स्कूटर, दो मोबाइल फोन, एक बैग और दो पर्स बरामद किया। इसी तरह एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों ने प्रीपाक (प्रो) के एक सक्रिय कैडर निंगथौजम कैनेडी (41) उर्फ गुली उर्फ अंगौसना को गिरफ्तार किया। उसे इंफाल ईस्ट जिला के पोरोम्पत थानांतर्गत क्षेत्र के खेवा बाजार से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया गया। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने बिश्नुपुर जिला के नांबोल थानांतर्गत मालोम तुलीहाल माखा लाईकाई क्षेत्र से एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान खॉइसनाम मोरेन्द्रजीत सिंह उर्फ कुमार (42) के रूप में की गयी है। इसके पास से एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने ककचिंग जिला के केइरक अवांग लूकोन चिंगोल क्षेत्र में एक सघन तलाशी अभियान चलाते हुए बड़ी मात्रा में हथियार एवं अन्य सामग्री बरामद की। बरामद सामग्रियों में मुख्य रूप से एक अमोघ कार्बाइन मैगजीन के साथ, दो स्थानीय निर्मित लाथोड़ बंदूकें, दो स्थानीय निर्मित सिंगल बैरल्स बंदूक, सात आंसू गैस के शेल, तीन ट्यूब लॉन्चिंग उपकरण, दो प्वाइंट 36 एचई ग्रेनेड दो डेटोनेटर के साथ, 50 राउंड्स गोलियां, 100 खाली केस, दो आईडीएल विस्फोटक दो डेटोनेटर के साथ, दो हेलमेट, एक बीपी जैकेट, और दो मैगजीन पाउच शामिल हैं।

इसके अलावा मणिपुर के विभिन्न जिलों में गुरुवार को पहाड़ों और घाटी में कुल 105 नाका/चेकपॉइंट लगाए गए और वाहनों की तलाशी ली गई।

गुजरात के कुंभघाट पर ट्रक-ईको की टक्कर में सात की मौत

वलसाड। गुजरात के वलसाड जिले के कपराडा तहसील स्थित कुंभघाट के वापी-धरमपुर मार्ग पर शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रक और ईको कार के बीच टक्कर में 07 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग कपराडा के आंबा जंगल गांव के एक ही परिवार के सदस्य थे। वे कपराडा से नानापोंढा की ओर जा रहे थे, तभी कुंभघाट के पास यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ईको कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह दब गया और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस गए। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को किसी तरह बाहर निकाला। मृतकों में 5 पुरुष, 01 महिला और 01 बच्ची शामिल हैं। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। अभी उनके नाम नही पता चल सके हें। गांव में मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

अवामी लीग पर प्रतिबंध को लेकर शेख हसीना के बेटे ने उठाए सवाल, अध्यादेश की वैधता पर बहस तेज

एजेंसी (हि.स.)
वॉशिंगटन

बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पुत्र सजीब वाजेद ने अवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर अंतरिम सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि नई बीएनपी-नेतृत्व वाली सरकार के सामने 30 दिनों की संवैधानिक समय-सीमा है, जिसके भीतर उसे इस अध्यादेश पर फैसला करना होगा।

वाजेद ने एक बयान में कहा कि अंतरिम सरकार ने एंटी टेररिज्म एक्ट 2009 में संशोधन करने के लिए एक नया अध्यादेश जारी किया, जिससे उसे किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिल गया। इसी आधार पर एस.आर.ओ. 137एआईएन/2025 जारी कर अवामी लीग पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 93(2) का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी अध्यादेश को नई सरकार के गठन के बाद संसद के पहले सत्र में पेश करना अनिवार्य है। यदि 30 दिनों के भीतर संसद उस अध्यादेश को कानून के रूप में पारित नहीं करती, तो वह स्वतः निरस्त हो जाएगा। वाजेद के अनुसार, बीएनपी-नेतृत्व वाली सरकार के पास दो विकल्प हैं—या तो वह अध्यादेश को समाप्त होने दे, या फिर उसे विधायी मंजूरी देकर स्थायी कानून में शामिल कर दे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संसद मौजूदा रूप में संशोधन को मंजूरी देती है, तो अवामी लीग को 'इकाई' के रूप में प्रतिबंधित करने और निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण रद्द करने जैसी कार्रवाइयाँ न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यदि संसद इस संशोधन को पारित करती है, तो यह आतंकवाद-रोधी कानून के असाधारण उपयोग का समर्थन माना जाएगा और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वाजेद ने कहा कि यदि नई सरकार अध्यादेश को मंजूरी नहीं देती तो यह अंतरिम प्रशासन की कठोर नीति से दूरी बनाने और बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के लिए स्थान बहाल करने का संकेत होगा।

नेपाल के पूर्व पीएम ओली के साथ चुनावी गठबंधन करने से आरपीपी का इनकार

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल में 05 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ना राजनैतिक भूल होगी। झापा 3 से प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ रहे आरपीपी के अध्यक्ष लिंगदेन ने कहा कि पिछले तीन चुनाव में झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र से केपी ओली अपने अकेले दम पर नहीं, बल्कि आरपीपी के समर्थन से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब पहली बार संविधान सभा के निर्वाचन में ओली को आरपीपी का समर्थन नहीं था, तो वो पराजित हो गए थे। उसके बाद हुए दूसरे संविधान सभा के निर्वाचन से लेकर 2017 और 2022 के प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में आरपीपी के समर्थन से ओली लगातार उस क्षेत्र से चुनाव जीतते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र में अब आरपीपी किसी भी तरह का गठबंधन या तालमेल नहीं करेगा और वह अपनी ताकत में जीत हासिल करेंगे। आरपीपी इस बार के चुनाव में ओली के चुनावी गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा चुकी है। लिंगदेन ने कहा कि चुनाव के कुछ दिन बाद ही ओली की तरफ से गठबंधन का प्रस्ताव आया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया है। आरपीपी के चुनावी गठबंधन से इंकार के बाद इस बार झापा 5 से ओली की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई है। इस बार देशव्यापी रूप से पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के बजाए वो शुरू से ही अपने क्षेत्र में ही डटे हुए हैं। इससे भी ओली के चुनाव में नतीजा के प्रति चिंता को स्पष्ट करता है।

साझेदार

चीन के साथ सबसे अधिक घाटा

नेपाल का भारत से आयात व्यापार बढ़ा

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल के आयात व्यापार में पड़ोसी देश भारत का एकाधिकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 के आखिरी छमाही तक नेपाल ने केवल भारत से ही 62,929 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सामान आयात किए हैं, जो कुल आयात का आधे से अधिक हिस्सा है। भारत के बाद चीन दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जहां से 23,538 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया है।

नेपाल ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 412 करोड़ रुपये, अमेरिका से 1744 करोड़ रुपये और इंडोनेशिया से 1283 करोड़ रुपये का सामान आयात क्या है। नेपाल के साथ व्यापारिक संबंधों वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूक्रेन और हांगकांग भी

शामिल हैं। इन देशों से होने वाले आयात की तुलना में नेपाल का निर्यात हिस्सा अत्यंत कम है। निर्यात की स्थिति पर नजर डालें, तो नेपाल का सबसे बड़ा बाजार भी भारत ही है। सात महीनों में नेपाल ने भारत को 13,751 करोड़ रुपये मूल्य के सामान निर्यात किए हैं। हालांकि, भारत के साथ व्यापार घाटा 49,177 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। निर्यात के मामले में दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जहां 1127 करोड़ रुपये मूल्य के नेपाली सामान निर्यात हुए हैं। इसी तरह, यूरोपीय देश जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम क्रमशः तीसरे और चौथे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बने हैं, जहां 289 करोड़ और 179 करोड़ रुपये मूल्य के नेपाली उत्पाद पहुंचे हैं। जापान, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, चीन और इटली भी नेपाल के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में शामिल हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि नेपाल चीन के साथ व्यापार में सबसे बड़ा असंतुलन झेल रहा है। चीन से 23,538 करोड़ रुपये से अधिक का आयात होने के बावजूद वहां निर्यात केवल 90 करोड़ रुपये तक सीमित रहा है।

इसी प्रकार यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी नेपाल का व्यापार घाटा काफी अधिक है। शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में भारत और अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों को होने वाला निर्यात अरबों के स्तर पर बहुत कम है। समग्र रूप से देखा जाए तो आयात की तुलना में निर्यात की वृद्धि दर अत्यंत धीमी रहना और व्यापार का कुछ सीमित देशों तक ही केंद्रित होना, नेपाल की अर्थव्यवस्था में बढ़ते व्यापार घाटे के जोखिम को और अधिक स्पष्ट करता है।

होबार्ट चरण में नई ऊर्जा के साथ वापसी को तैयार भारतीय पुरुष हॉकी टीम

कप्तान हार्दिक सिंह के नेतृत्व में स्पेन और ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

भारतीय पुरुष हॉकी टीम अब एफआईएच प्रो लीग के होबार्ट चरण पर फोकस कर चुकी है, जो 20 से 25 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया हॉकी सेंटर में खेला जाएगा। भारतीय टीम स्पेन और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन कर नई शुरूआत करने के इरादे से उतरेगी।

राउरकेला चरण से मिले अनुभवों के बाद भारतीय टीम ने सकारात्मक सोच के साथ खुद को फिर से तैयार किया है। आगामी मुकाबलों को टीम संयोजन परखने, रणनीति को मजबूत करने और इस साल होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप तथा एशियाई खेलों से पहले लय हासिल करने के अहम अवसर के रूप में देखा जा रहा है। 24 सदस्यीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा प्रतिभाओं को भी

शामिल किया गया है।

भारत अपने अभियान की शुरूआत 21 फरवरी को स्पेन के खिलाफ करेगा, इसके बाद 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। 24 फरवरी को एक बार फिर स्पेन से मुकाबला होगा, जबकि 25 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम मैच खेला जाएगा।

हालिया रिकॉर्ड दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर का संकेत देते हैं। स्पेन के साथ पिछले 10 मुकाबलों में दोनों टीमों ने चार-चार जीत दर्ज की हैं, जबकि दो मैच ड्रॉ रहे, जिन्हें भारत ने शूटआउट में जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आंकड़े मेजबान टीम के पक्ष में हैं, जहां पिछले 10 मैचों में उसे छह जीत मिली हैं, जबकि भारत ने दो मुकाबले जीते और दो ड्रॉ रहे।

दो बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हार्दिक सिंह को इस चरण के लिए कप्तान बनाया गया है। टीम में अमनदीप लकड़ा, मनमीत सिंह, अंगद वीर सिंह, अरिजीत सिंह हुंडाल और आदित्य अर्जुन लालगे जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने के लिए उत्सुक हैं।

कप्तान हार्दिक सिंह ने कहा कि टीम सकारात्मक और आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरेगी तथा युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा टीम के प्रदर्शन में नई धार जोड़ेगी। भारतीय टीम हॉबर्ट चरण में मजबूत प्रदर्शन कर बड़े टूर्नामेंटों से पहले आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी।

ब्रिटिश ओलंपियन कीली हॉजकिंसन ने तोड़ा 800 मीटर का विश्व इंडोर रिकॉर्ड

लीविन (फ्रांस)। ब्रिटेन की ओलंपिक चैंपियन कीली हॉजकिंसन ने महिलाओं की 800 मीटर स्पर्धा में नया विश्व इंडोर रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अनुसार उन्होंने गुरुवार को वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर टूर गोल्ड मीट में 1:54.87 मिनट का समय निकालते हुए स्लोवेनिया की योलांडा चेपलाक का लगभग 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। चेपलाक ने 3 मार्च, 2002 को 1:55.82 मिनट का समय लेकर यह रिकॉर्ड बनाया था। हॉजकिंसन ने इस समय को 0.95 सेकंड से बेहतर करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। स्विट्जरलैंड की ऑड्रे वेरो दूसरे स्थान पर रहीं, लेकिन वह ब्रिटिश धाविका से काफी पीछे थीं। दौड़ की शुरूआत से ही 23 वर्षीय हॉजकिंसन ने बढ़त बना ली थी। उन्होंने 200 मीटर 26.47 सेकंड में और 400 मीटर 55.56 सेकंड में पूरा किया। 600 मीटर तक पहुंचते-पहुंचते (1:25.06) वह अन्य धाविकाओं से काफी आगे निकल चुकी थीं। रिकॉर्ड बनाने के बाद हॉजकिंसन ने दर्शकों का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें पूरे स्टेडियम से मिल रहा समर्थन साफ सुनाई दे रहा था। हॉजकिंसन ने 2021 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और इसके बाद पेरिस 2024 ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

भावुक जोनाथन ट्रॉट ने अफगानिस्तान के साथ अपने सफर को कहा अलविदा

'संयोग' से शुरू हुई थी कोचिंग यात्रा

एजेंसी (हि.स.)

चेन्नई

अफगानिस्तान के मुख्य कोच जोनाथन ट्रॉट ने 2026 टी20 विश्व कप में टीम के अंतिम ग्रुप मुकाबले के बाद अपने कार्यकाल को भावुक अंदाज में अलविदा कहा। कनाडा के खिलाफ जीत के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में 44 वर्षीय ट्रॉट अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने स्वीकार किया कि अफगानिस्तान के साथ उनकी यात्रा ह्यसंयोग से शुरू हुईह्न, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन के सबसे संतोषजनक अध्यायों में से एक रहा।

अफगानिस्तान ने अपने अंतिम ग्रुप मैच में कनाडा को हराया। इस मुकाबले में इब्राहिम जदरान 95 रन की नाबाद पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच बने। उन्होंने अपना पुरस्कार कोच ट्रॉट को समर्पित किया और विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने बैठकर अपने कोच को भावुक होते देखा। जोनाथन ट्रॉट ने 2022 में अफगानिस्तान टीम की कमान संभाली थी। उन्होंने खुलासा

किया कि मूल रूप से यह पद ग्राहम थॉर्प को संभालना था, लेकिन परिस्थितियों के चलते वह यह जिम्मेदारी नहीं ले सके। इसके बाद ट्रॉट को यह अवसर मिला। उन्होंने कहा, मुझे यह मौका संयोग से मिला। ग्राहम थॉर्प ने मेरे कोचिंग करियर के विकास में बड़ी भूमिका निभाई थी। जब यह जिम्मेदारी मिली तो मैंने इसे दोनों हाथों से स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से काम किया। ट्रॉट ने अपने कार्यकाल की कई यादगार उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने विश्व कप में पहली बार पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड को मात दी और पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ विदेशी सरजमीं पर द्विपक्षीय सीरीज जीती। हालांकि 2026 टी20 विश्व कप में टीम 2024 जैसी सफलता दोहराने में सफल नहीं रही, लेकिन ट्रॉट ने परिणामों से अधिक टीम के मानवीय विकास को अहम बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पहली बार इब्राहिम जदरान, अजमतुल्लाह उमरजई और रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ियों को देखा, तो उनकी प्रतिभा ने प्रभावित किया। ट्रॉट ने बताया कि अफगानिस्तान की असली ताकत केवल उनके स्पिन गेंदबाज नहीं, बल्कि टीम के रूप में उनका विकास है। उन्होंने कहा कि जब वह पहली बार टीम के साथ आयरलैंड दौरे पर गए थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि खिलाड़ियों में अपार प्रतिभा है, लेकिन उन्हें केवल संरचना और पेशेवर रवैये की जरूरत है। उन्होंने कहा, थोड़ी-सी संरचना, पेशेवर मानसिकता और उच्च मानक जोड़ने से बड़ा बदलाव आया। आज की टीम और पहले की टीम में जमीन-आसमान का अंतर है, । ट्रॉट ने यह भी रेखांकित किया कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी सीमित संसाधनों में खेलते हैं। उनके पास स्थायी घरेलू मैदान, आधुनिक अकादमियां और बुनियादी ढांचे की वैसी सुविधाएं नहीं हैं जैसी अन्य बड़ी टीमों के पास हैं।

श्रीलंका को हराकर एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पहुंची इंडिया ए

एजेंसी (हि.स.)

बैंकॉक

इंडिया ए महिला क्रिकेट टीम ने एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में श्रीलंका ए महिला क्रिकेट टीम को पांच विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। यह मुकाबला बैंकॉक के टर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। अब फाइनल में भारत का सामना 22 फरवरी को बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा।

कप्तान राधा यादव ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। उन्होंने 19 रन देकर चार विकेट झटके और फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 गेंदों पर नाबाद 31 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ए की टीम 118 रन पर सिमट गई। राधा के अलावा तनुजा कंवर और प्रेमा रावत ने दो-दो विकेट लेकर रनगति पर नियंत्रण रखा।

सेमीफाइनल में श्रीलंका ए को पांच विकेट से हराया

जवाब में वृंदा दिनेश ने 20 गेंदों पर तेज 42 रन बनाकर भारत को मजबूत शुरूआत दी। बीच में कुछ विकेट गिरने के बावजूद राधा की आक्रामक पारी ने टीम को जीत तक पहुंचा दिया।

कार्लोस अल्कराज ने कतर ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह, जैनिक सिनर बाहर

दोहा। कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में गुरुवार को खेले गए क्वार्टरफाइनल मुकाबलों में रोमांच चरम पर रहा। स्पेन के स्टार खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने करेन खाचानोव को कड़े संघर्ष में हराकर अंतिम चार में प्रवेश किया, जबकि इटली के जैनिक सिनर को याकुब मेंसिक के हाथों हार झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे अल्कराज ने खाचानोव को 6-7 (3/7), 6-4, 6-3 से मात दी। पहला सेट टाई-ब्रेक में गंवाने के बाद उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अगले दो सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। अब सेमीफाइनल में अल्कराज का सामना आंद्रे रुबलेव से होगा। रुबलेव ने अपने क्वार्टरफाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 7-6 (7/2) से हराया। दूसरी ओर, विश्व नंबर दो सिनर का अभियान यहीं समाप्त हो गया। उन्हें छठी वरीयता प्राप्त याकुब मेंसिक ने 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 से पराजित किया। मेंसिक ने जीत के बाद कहा कि वह मुकाबले में जीत की मानसिकता के साथ उतरे थे। अब सेमीफाइनल में उनका सामना फ्रांस के आर्थर फिल्स से होगा, जिन्होंने जिरी लेहेका को सीधे सेटों में हराकर अंतिम चार में जगह बनाई।

एफआईएच प्रो लीग विवाद : पाकिस्तान ने हॉकी टीम के कप्तान अम्माद बट पर लगा दो साल का प्रतिबंध रद्द किया

एजेंसी (हि.स.)

इस्लामाबाद

पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट पर लगाया गया दो साल का प्रतिबंध रद्द कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (पीएचएफ) द्वारा लगाया गया यह प्रतिबंध सरकार ने 'गैरकानूनी और असंवैधानिक' करार दिया है।

पीएचएफ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से ठीक पहले तारिक बुगती ने अम्माद शकील बट को फेडरेशन की आलोचना करने के आरोप में दो साल के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हॉकी से प्रतिबंधित कर दिया था। बट ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान हुई अव्यवस्थाओं को लेकर फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाए थे।

हालांकि, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा संरक्षक-इन-चीफ नियुक्त किए गए पीएचएफ के अंतरिम अध्यक्ष मुहयुद्दीन अहमद वानी ने बुगती के इस

फैसले को पलटते हुए इसे गैरकानूनी और असंवैधानिक कदम बताया। ऑस्ट्रेलिया दौरे से टीम की वापसी के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कैनबरा में खेले गए एफआईएच प्रो लीग मुकाबलों के दौरान टीम को भारी लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। राज्य संचालित पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड (पीएसबी) द्वारा टीम के लिए पांच सितारा होटल में ठहरने हेतु एक करोड़ रुपये जारी किए जाने के बावजूद खिलाड़ियों को एयरबीएनबी आवास में ठहरना पड़ा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुगती का इस्तीफा तुरंत स्वीकार करते हुए मुहयुद्दीन अहमद वानी को पीएचएफ का एड-हॉक अध्यक्ष और ब्रिगेडियर मुसरतुल्लाह को महानिदेशक नियुक्त किया है। दोनों फिलहाल अस्थायी रूप से हॉकी मामलों का प्रबंधन करेंगे। बुधवार तड़के टीम की स्वदेश वापसी के बाद अम्माद बट और अन्य वरिष्ठ खिलाड़ियों ने हवाई अड्डे पर मीडिया से कहा था कि वे मौजूदा प्रबंधन के साथ काम जारी नहीं रख सकते। बट ने खुलासा किया कि खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में अपनी समस्याओं पर मीडिया से बात न करने की धमकी दी गई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि दौरे के दौरान खिलाड़ियों को 'रसोई साफ करने और बर्तन धोने' के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, जिस होटल में टीम के ठहरने की व्यवस्था की गई थी, वहां अग्रिम भुगतान न होने के कारण प्रवेश से मना कर दिया गया, जिसके चलते खिलाड़ियों को घंटों सड़क पर इंतजार करना पड़ा। बट ने यह भी दावा किया कि अधिकांश खिलाड़ियों को पिछले एक साल से दैनिक भत्ता नहीं मिला है।

बीसीसीआई महिला इंटर-जोनल वनडे टूर्नामेंट नोर्थ जोन से हिमाचल की सुषमा वर्मा का चयन

एजेंसी (हि.स.)

धर्मशाला

बीसीसीआई महिला सीनियर इंटर-जोनल वनडे टूर्नामेंट 2025-26 के लिए उत्तरी क्षेत्र की टीम में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) से सुषमा वर्मा का चयन हुआ है। इसके अलावा स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शिवानी सिंह और ज्योति ठाकुर शामिल हैं। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) 5 से 15 मार्च 2026 तक बेंगलुरु में सीनियर महिला इंटर-जोनल वनडे ट्रॉफी का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में सीनियर महिला उत्तरी क्षेत्र चयन समिति की बीते दिन जम्मू में हुई बैठक में खिलाड़ियों का चयन किया गया। वहीं अगर प्रतियोगिता के मुकाबलों की बात करें पहला मैच उत्तर क्षेत्र बनाम दक्षिण क्षेत्र 5 मार्च को, उत्तर क्षेत्र बनाम पश्चिम क्षेत्र 7 मार्च, पूर्वी क्षेत्र बनाम उत्तर क्षेत्र 9 मार्च, मध्य क्षेत्र बनाम उत्तर क्षेत्र 11 मार्च, पूर्वोत्तर क्षेत्र बनाम उत्तरी क्षेत्र 13

मार्च को जबकि फाइनल 15 मार्च को बेंगलुरु में ही खेला जाएगा।

एचपीसीए के सचिव मनुज शर्मा ने बताया कि उत्तरी क्षेत्र की टीम में वरिष्ठ खिलाड़ी सुषमा वर्मा का चयन हुआ है जबकि शिवानी सिंह और ज्योति ठाकुर को स्टैंडबाय रखा गया है। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को एचपीसीए की ओर से शुभकामनाएं दी हैं।

दर्पण विशेष

भाषा वह डोर है जो सभी को एक साथ बांधती है

भाषा वह डोर है जो सभी को एक साथ बांधती है। इसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। भाषा मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों का आदान-प्रदान करता है। दुनिया भर के कई देशों, राज्यों, कस्बों और क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। कहीं धार्मिक भाषा का अंदाज अलग है तो कहीं बातचीत का लहजा अलग है। लेकिन इसके बावजूद हर भाषा लोगों से संवाद करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा वह डोर है जो सभी को एक साथ बांधती है। इस बंधन को मजबूत करने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीयमातृभाषा दिवस मनाया जाता है।

कैसे हुई थी अंतरराष्ट्रीयमातृभाषा दिवस की शुरूआत

यह दिन बांग्लादेश द्वारा अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए किए गए लंबे संघर्ष की याद में मनाया जाता है। साल 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकताओं ने बांग्ला मातृभाषा के अस्तित्व के लिए धरना प्रदर्शन शुरू किया था। देखते ही देखते यह प्रदर्शन एक नरसंहार में बदल गया। जिसे रोकने के लिए तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई, जिससे कई और लोगों की भी जानें गई। बांग्लादेश सरकार के अस्तित्व में आने के बाद बांग्लादेश सरकार ने यूनेस्को के सामने एक प्रस्ताव रखा। साल 1999 में यूनेस्को ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन इस पहली बार साल 2000 में मनाया गया था।

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इतिहास

दरअसल, 21 फरवरी 1952 के दिन ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों और कुछ सामाजिक कार्यकताओं ने अपनी मातृभाषा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। यह विरोध जल्द ही नरसंहार में बदल गया जब तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दीं। इस घटना में 16 लोगों की जान चली गई। 1999 में यूनेस्को ने इस बड़े भाषा आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह कहा जा सकता है कि बांग्ला भाषियों के अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम के कारण ही आज विश्व में अंतरराष्ट्रीयमातृभाषा दिवस मनाया जाता है।

भाषाओं में संस्कृति और सभ्यता झलकती है

दुनिया भर में अलग-अलग जातियों, धर्मों, संप्रदायों और अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। इन मतभेदों के पीछे एकता और समानता है जो सभी को एक साथ बांधती है। भाषा वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति की संस्कृति और सभ्यता झलकती है। अंतरराष्ट्रीयमातृभाषा दिवस सांस्कृतिक विविधता और विभिन्न भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोगों में न केवल अपनी और दूसरों की भाषाओं के प्रति प्रेम विकसित हो बल्कि विभिन्न मातृभाषाओं के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो सके। विभिन्न भाषाएँ विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ती हैं। जिससे संचार करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है।

मातृभाषाओं का महत्व

मातृभाषा वह भाषा है जो लोग बचपन में अपने माता-पिता या देखभाल करने वालों से सीखते हैं। ये आम तौर पर पहली भाषाएं हैं जिन्हें लोग बोलते हैं और जिनका उपयोग वे अपने परिवार और समुदाय के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। मातृभाषाएं अनेक कारणों से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, वे किसी की पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, क्योंकि वे किसी की संस्कृति, मूल्यों और विश्वदृष्टि को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा, वे संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को जानकारी प्राप्त करने और संसाधित करने, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने और महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। तीसरा, उनका शिक्षा और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सीखने, संचार और भागीदारी की सुविधा प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुरूआत की कहानी

मातृभाषा मनाने के पीछे बांग्लादेश के संघर्ष की एक लम्बी कहानी है। दरअसल इस दिन बांग्लादेश ने अपनी मातृभाषा की रक्षा की थी जिसकी याद में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दरअसल साल 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के साथ ही सामाजिक कार्यकताओं ने भी अपनी परवाह न करते हुए बांग्ला मातृभाषा के अस्तित्व को बचाने के लिए धरना-प्रदर्शन देना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे धरना-प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि इसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। धरना-प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया उन्होंने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं जिससे न जानें कितने ही स्टूडेंट्स और सामाजिक कार्यकताओं ने अपनी जान गवां दी। इसके बाद बांग्लादेश सरकार बनी और बांग्लादेश सरकार ने वठएरउड के सामने एक प्रोप्सल रखा। प्रस्ताव में आज के दिन को अंतरराष्ट्रीयमातृभाषा दिवस के रूप में घोषित करने के लिए कहा गया। वठएरउड ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए साल 17 नवम्बर 1999 में पहली बार अंतरराष्ट्रीयमातृभाषा दिवस सेलिब्रेट करने का ऐलान किया। भले ही इसकी घोषणा साल 1999 में की गई हो लेकिन पहली बार अंतरराष्ट्रीयमातृभाषा दिवस साल 2000 में मनाया गया।

दुनियाभर में कितनी भाषाएं हैं

यदि हम दुनियाभर की भाषाओं के बारे में बात करें तो इनकी कितना संख्या है यह गिनना मुश्किल है लेकिन वठएरउड के मुताबिक सम्पूर्ण विश्व में लगभग सात हजार भाषाएं बोलीं जाती हैं। और यदि अकेले भारत की बात करें तो यहां 19,500 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी भाषाओं को मातृभाषा के रूप में यहां जाना जाता है। वठएरउड के अनुसार, दुनियाभर में बोली जाने वाली सभी 7,000 भाषाओं में से 90 प्रतिशत ऐसी भाषाएँ हैं जिनका इस्तेमाल पूरे एक लाख लोग भी नहीं करते हैं। दुनियाभर में लगभग 11 लाख लोग ऐसे हैं जो कुल 150-200 भाषाओं को जानते हैं और उन्हीं में बात भी करते हैं। इसके अलावा हमारे देश भारत में कुल 121 वे बोलियां हैं जिन्हें कुल 12 या 13 हजार लोग ही बोलते हैं। वठएरउड के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में 40 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं करते हैं और न ही उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पुरे एशिया में दुनिया भर की 2,200 भाषाएँ बोली जाती हैं जबकि अकेले यूरोप में दुनियाभर की 260 भाषाएं बोली जाती हैं।

राज्यपाल ने 'जीरो वेस्ट' तीन दिवसीय रोज फेस्टिवल का किया उद्घाटन

54वां रोज फेस्टिवल-2026 जाकिर हुसैन रोज गार्डन में भव्य शुभारंभ

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

54वां रोज फेस्टिवल-2026 आज प्रतिष्ठित जाकिर हुसैन रोज गार्डन में धूमधाम और भव्यता के साथ प्रारंभ हुआ। प्रकृति को समर्पित इस तीन दिवसीय महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी धर्मपत्नी अनीता कटारिया के साथ किया।

उद्घाटन समारोह में शहर के मेयर सौरभ जोशी, यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, गृह सचिव-सह-सचिव स्थानीय सरकार मंदीप सिंह बराड़, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, मुख्य वन संरक्षक सौरभ कुमार, विशेष आयुक्त प्रदीप कुमार, पार्षदगण, प्रशासन एवं नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नगर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की सराहना की।उन्होंने कहा कि प्रत्येक फूल का अपना आकर्षण होता है, किंतु गुलाब को 'फूलों की रानी' कहा जाता है, जो प्रेम, करुणा और शाश्वत सौंदर्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रोज गार्डन इस प्रकार विकसित किया गया है कि उसमें टहलना मानो एक सुंदर कहानी पढ़ने जैसा अनुभव देता है। राज्यपाल ने रोज फेस्टिवल की परिकल्पना करने वाले एम. एस. रंधावा तथा जिनके नाम पर इस उद्यान का नाम रखा गया, डॉ. जाकिर हुसैन को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया और उन्हें प्रकृति एवं बागवानी का सच्चा प्रेमी बताया। नागरिकों और युवा प्रतिभाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी की सराहना करते हुए उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों के लिए 10 लाख के विशेष पुरस्कार कोष की घोषणा की। उन्होंने यह भी प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष भी महोत्सव लगातार दूसरी बार 'जीरो बजट' और 'जीरो वेस्ट' मॉडल पर आयोजित किया जा रहा है, जो सतत विकास और जनभागीदारी के प्रति शहर की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि महोत्सव में हर आयु वर्ग के लिए आकर्षण है, जिसमें रोज प्रिंस एवं प्रिंसेस, मिस्टर एवं मिस रोज तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोज किंग एवं क्वीन जैसी लोकप्रिय प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के अथक प्रयासों की सराहना की।नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि रोज गार्डन में वर्तमान में 800 से अधिक किस्मों के गुलाब विभिन्न रंगों में खिले हुए हैं, जिनके साथ आकर्षक पुष्प सज्जा और विशेष प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं।

तीन दिवसीय इस महोत्सव में ब्रास एवं पाइप बैंड प्रतियोगिताएं, फोटोग्राफी प्रदर्शनी, मुशायरा, सांस्कृतिक संध्या तथा बच्चों के लिए विशेष गेम जोन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 'जीरो वेस्ट' थीम को सुदृढ़ करते हुए नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जागरूकता प्रदर्शनी लगाई है तथा 'स्वच्छता के पजल्स' नामक इंटरैक्टिव गतिविधि शुरू की है, जो कचरा पृथक्करण, चार प्रकार के अपशिष्ट, प्लास्टिक मुक्त जीवन और स्वच्छता संदेशों को बढ़ावा देती है।इसके अतिरिक्त, 'एमसी वन पास' पहल के प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख प्रवेश द्वारों पर विशेष स्टॉल भी लगाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना की जानकारी मिल सके।

पीएचडीसीसीआई में आयोजित इंटरैक्टिव सत्र में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मिली नई मजबूती

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (एमसीए), भारत सरकार तथा एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया (एसीपीआई) के सहयोग से 'रीजनल डायरेक्टर के समक्ष प्रोफेशनल्स के लिए अवसर' विषय पर एक इंटरैक्टिव सत्र का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम पीएचडी हाउस, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। इस सत्र का नेतृत्व रीजनल एनसीएलटी एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर सीएस राहुल जोगी ने किया।वे पूरे नॉर्दर्न रीजन में रेगुलेटर्स और प्रोफेशनल्स के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रोफेशनल्स को एक साझा मंच पर लेकर आया, जहां रचनात्मक संवाद हुआ। इस सत्र को संबोधित करते हुए, सीएस राहुल जोगी ने कॉर्पोरेट रेगुलेटरी और क्वासी-ज्यूडिशियल मामलों में प्रोफेशनल्स के बढ़ते दायरे और बदलती जिम्मेदारियों पर जोर दिया। इस सत्र में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में रीजनल डॉयरेक्टर (एनआर-II) आरसी मिश्रा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हरियाणा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज संजय वर्मा ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने और समय पर कानूनी नियमों का पालन पक्का करने में कंपनी सेक्रेटरी और दूसरे प्रोफेशनल्स की अहम भूमिका पर जोर दिया।

पीएचडीसीसीआई की सीनियर रीजनल डायरेक्टर भारती सूद ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ हुए इस सहयोग की सराहना की। इस अवसर पर पीएचडीसीसीआई टीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को चंडीगढ़ में रीजनल डायरेक्टर (एनआरझ्रक्क) और हरियाणा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के नए कार्यालय के संचालन शुरू होने पर बधाई दी। रीजनल डायरेक्टर कार्यालय का खुलना इस बात का संकेत है कि संस्थागत स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि हरियाणा और आसपास के राज्यों के बढ़ते कॉर्पोरेट और औद्योगिक माहौल के अनुसार नियामकीय ढांचे को मजबूत और व्यवस्थित किया जा सके। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कमेटी के को-कन्वीनर सीएस अर्षदीप जज ने कहा कि ऐसे इंटरैक्टिव कार्यक्रम प्रोफेशनल्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं।इससे उन्हें नियमों और प्रक्रियाओं को सीधे अधिकारियों से समझने का मौका मिलता है। सत्र का समापन प्रतिभागियों और अधिकारियों के बीच हुई रोचक बातचीत के साथ हुआ। इस अवसर पर सीएस राहुल जोगी के सक्रिय नेतृत्व में पीएचडीसीसीआई ने नॉर्दर्न रीजन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नियामकीय जागरूकता और पेशेवर उत्कृष्टता को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

छात्राओं ने नेचर कैंप थापली में सीखे वन, वन्यजीव और इको-टूरिज्म के गुर

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आज भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं ने नेचर कैंप थापली में आयोजित दो दिवसीय शैक्षणिक एवं साहसिक भ्रमण कार्यक्रम में भाग लिया।युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के तहत यह दो दिवसीय विशेष ट्रैकिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। दूसरे दिन छात्राओं ने ट्रैकिंग गतिविधि में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए प्रकृति के निकट रहकर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।कैंप के दौरान डेप्युटी रेंज अधिकारी विजय नेहरा ने 'वन, वन्यजीव एवं जलवायु परिवर्तन' विषय पर व्याख्यान दिया। हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित सात दिवसीय ट्रैकिंग अभियान के तहत आज विद्यार्थियों का दल सिंहवाला गांव से आदि बद्री तक ट्रैकिंग करेंगे। 153 किलोमीटर लम्बी ट्रैकिंग कालका से शुरू होकर कलेसर मे जाकर समाप्त होगी। इस अभियान में भाग ले रहे विद्यार्थी सात दिनों में इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक को पूरा करेंगे। युवा कल्याण संयोजक नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह ट्रैकिंग कार्यक्रम युवाओं में साहस, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता एवं शारीरिक दक्षता विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को साहसिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट शिशु गृह, सेक्टर-15, पंचकूला का किया औचक निरीक्षण

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

अजय कुमार घनघस ने गांव रत्तेवाली का भी किया औचक दौरा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला, अजय कुमार घनघस ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट शिशु गृह, सेक्टर-15, पंचकूला का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य संस्थान के समग्र कार्य-प्रणाली, देखभाल के मानकों तथा अभिलेखों के संधारण की समीक्षा करना था।

निरीक्षण के दौरान सीजेएम ने स्टाफ के लिए बनाए गए उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया और सुनिश्चित किया कि उसमें नियमित रूप से सही एंट्री की जा रही हैं।उन्होंने संस्थान में रह रहे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली की भी जांच की और निर्देश दिए कि सभी कैमरे निरंतर क्रियाशील रहें तथा निर्धारित नियमों के अनुसार फुटेज सुरक्षित रखी जाए। घनघस ने रसोईघर का निरीक्षण करते हुए भोजन तैयार करने की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने रसोईघर की स्वच्छता, खाद्य सामग्री के भंडारण तथा समग्र स्वच्छता मानकों की जांच की और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप बच्चों को पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने पर बल दिया। सीजेएम ने बच्चों के आवासीय कक्षों का भी अवलोकन किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से बातचीत कर प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण एवं दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। संस्थान द्वारा मेंटेंन किए गए मेडिकल रिकॉर्ड एवं अन्य आवश्यक रजिस्टरों की भी जांच की गई। पारदर्शिता और फंड के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु खातों एवं दान से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई।

स्टाफ से संवाद करते हुए अजय कुमार घनघस ने उन्हें संवेदनशीलता एवं समर्पण के साथ अपने दायित्व निभाने के निर्देश दिए और कहा कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रह रहे बच्चों को विशेष देखभाल, स्नेह एवं सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उन्होंने स्टाफ के प्रयासों की सराहना करते हुए उच्च स्तर की देखभाल एवं जवाबदेही बनाए रखने पर भी जोर दिया।इसके उपरांत घनघस ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, पंचकूला के अंतर्गत स्थापित लीगल एड क्लिनिक की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने हेतु गांव रत्तेवाली का भी औचक दौरा किया।इस अवसर पर गांव के सरपंच भी उपस्थित रहे। सीजेएम ने क्लिनिक में तैनात पैनल अधिवक्ताओं एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स की उपस्थिति तथा नियमितता के संबंध में जानकारी ली।उन्होंने सरपंच एवं उपस्थित पैरा लीगल वॉलंटियर्स को निर्देश दिए कि क्लिनिक में कानूनी परामर्श हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का व्यवस्थित रजिस्टर तैयार किया जाए। प्रत्येक आगंतुक का आधार नंबर, फोन नंबर, संक्षिप्त कानूनी विषय तथा अधिवक्ता/ पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा प्रदान की गई सलाह का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का दस्तावेजीकरण डीएलएसए को अधिवक्ताओं एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स के कार्य और प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी में सहायक होगा।

निपुण थर्ड पार्टी असेसमेंट मे जिला पंचकूला ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत फरवरी माह की जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई की बैठक का आयोजन प्रधानाचार्या डाइट सुजाता खत्री की अध्यक्षता में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हुआ जिसमें जिला एफएलएन समन्वयक व जिला पंचकूला में निपुण के नोडल अधिकारी असिन्द्र कुमार द्वारा पीपीटी के माध्यम से जिला पंचकूला के प्रदर्शन को दशार्या गया। समीक्षा बैठक में राज्य स्तरीय थर्ड पार्टी असेसमेंट के परिणामों को प्रस्तुत किया गया जिसमे लिट्रेसी में गद्यांश श्रवण बोध,गद्यांश चित्र बोध,शब्द पठन,वर्ण लेखन शब्द लेखन,मे विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। न्यूमीरेसी मे अंक व संख्या पहचान, मापन व संख्या तुलना मे विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह थर्ड पार्टी असेसमेंट अक्टूबर 2025 मे निदेशालय द्वारा जिले के 52 विद्यालयों मे करवाई गयी थी । इसके अतिरिक्त मार्च मे होने वाली एफ एल स्टडी व फाइनल असेसमेंट की तैयारियों का भी रिव्यु लिया गया व कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला परियोजना अधिकारी जोगिन्द्र लाठर, उप जिला शिक्षा अधिकारी नरोत्तम शर्मा, जिले के विभिन्न खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र मलिक, शालिनी कपूर, कर्मवीर शर्मा के अतिरिक्त चारों खण्डों के ब्लॉक एफ एल एन कोऑर्डिनेटर अंजलि चहल, सविता, प्रतिभा दूहन, शोभना, निपुण तकनीकी कोऑर्डिनेटर गीतिका, डाइट प्रवक्ता रश्मि, राज्य एस पी आई यू सदस्य निशा व करण सभरवाल, संपर्क फाउंडेशन से प्रमोद, उपस्थित रहे।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर आयोजित लेक्चर में प्रो. नाहर ने छात्रों को दी संवैधानिक अधिकारों की जानकारी

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज में शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट समाजशास्त्र विभाग की ओर से पीएम-उषा (रुसा) योजना के तहत विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर 'सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान' विषय पर एक विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर एवं डीन, सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स प्रो.इमेनुअल नाहर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरूआत कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा और समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष मोना अरोड़ा द्वारा मुख्य वक्ता को पौधा भेंट करने से हुई। इस कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षकों और लगभग 200 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रो. नाहर ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निहित सामाजिक न्याय के संविधानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुख्य संवैधानिक प्रावधानों जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए लागू सकारात्मक कार्रवाई नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों, विशेषकर हाशिए पर रहने वाले और कमजोर वर्गों के लिए समानता, गरिमा और न्याय को बढ़ावा देने का एक सशक्त उपकरण है। व्याख्यान में प्रो. नाहर ने सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में समकालीन चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिनमें जाति आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता और आर्थिक अंतर शामिल हैं।उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को समझें और एक अधिक न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाज बनाने में सक्रिय रूप से योगदान दें। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों और मुख्य वक्ता के बीच एक इंटरैक्टिव प्रश्न-उत्तर सत्र के साथ हुआ। इसके बाद समाजशास्त्र विभाग की प्रमुख मोना अरोड़ा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम ने आधुनिक समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में भारतीय संविधान की प्रासंगिकता के प्रति जागरूकता फैलाने में सफलता हासिल की।

अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टरों के लिए ड्रॉ का किया गया आयोजन

पंचकूला। जिला के कृषि विभाग द्वारा अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा जिले के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टरों के लिए ड्रॉ का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियन्ता, ओमप्रकाश महिवाल ने बताया की सभी चयनित किसान 5 दिन के अंदर-अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवा दें, जिनके निरीक्षण उपरांत किसानों को परमिट दे दिए जाएंगे।इसके बाद किसान सरकार द्वारा अनुमोदित कंपनियों से अपने ट्रैक्टर की खरीद कर सकते हैं।यदि किसी किसान का आवेदन किसी वजह रद्द से होता है तो प्रतीक्षा सूची में से अगले किसान का चयन कर लिया जाएगा। उन्होने बताया कि जिले के कुल 48 अनुसूचित जाति किसानों ने ट्रैक्टर के लिए आवेदन किया हुआ था जिनमें से 4 किसानों का ऑनलाइन ड्रॉ द्वारा चयन किया गया। चयनित किसानों में संजीव कुमार पुत्र धर्मपाल गांव टोका, मेहर सिंह हुडीया पुत्र पियारेलाल गांव वार्ड-8 एमसी पंचकूला, अतुल आर्य पुत्र राम किशन गांव वार्ड-10 एमसी पंचकूला एवं नरेश कुमार पुत्र जिता राम, गांव भूड, शामिल है। इस अवसर पर कृषि विभाग से रविन्द्र सिंह, उप कृषि निदेशक, ओमप्रकाश महिवाल सहायक कृषि अभियन्ता, अशोक कौशिक, जिला उद्यान अधिकारी सहित जीएसटी विभाग के प्रतिनिधि इत्यादि उपस्थित रहे।

टीडीबी आत्मनिर्भर यात्रा पंजाब चैप्टर ने उद्योग-अकादमिक सहयोग को दी नई गति

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा टीडीबी आत्मनिर्भर यात्रा पंजाब चैप्टर का आयोजन पंजाब राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा भारतीय उद्योग परिसंघ नॉर्दर्न रीजन के सहयोग से चंडीगढ़ में किया गया।इस कार्यक्रम में नीति-निमार्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स और शिक्षण संस्थानों की सक्रिय भागीदारी रही।

यह पहल पंजाब में नवाचार आधारित औद्योगिक विकास को गति देने, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण को प्रोत्साहित करने तथा उद्योग-स्टार्टअप अकादमिक समन्वय को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान पीएससीएसटी और टीडीबी के बीच भविष्य में संस्थागत सहयोग को और सुदृढ़ करने की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार-विमर्श भी हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीडीबी के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि बोर्ड देश में विकसित प्रौद्योगिकियों को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुँचाने में एक सेतु की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी मूल्यांकन और परियोजना निगरानी के माध्यम से नवाचारों को जोखिम से उबारकर उन्हें व्यावसायिक सफलता तक पहुँचाया जाता है। पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग के सचिव प्रियंक भारती, आईएएस ने राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य संस्थाओं के बीच तालमेल से प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमों को नई ऊर्जा मिलेगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख सत्र आयोजित किए गए

उद्योग एवं स्टार्टअप्स के लिए ळऊइ की वित्तीय सहायता तंत्र पात्रता, मूल्यांकन प्रक्रिया और समर्थित परियोजनाओं के अनुभव साझा किए गए। उद्योग-अकादमिक नेतृत्व संवाद नीतिगत आवश्यकताओं, तकनीकी वाणिज्यीकरण और सहयोग के व्यावहारिक मॉडल पर चर्चा। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल (ळफछ) और परिपक्वता के चरण अवधारणा से लेकर व्यावसायिक उपयोग तक की यात्रा पर मार्गदर्शन । स्टार्टअप यात्राः आइडिया से इम्पैक्ट तक विकास रणनीतियों और स्केल-अप के अनुभवों का साझा मंच। अंत में आयोजित ओपन हाउस चर्चा में प्रतिभागियों ने अपने सुझाव और प्रश्न रखे, जिससे भविष्य की पहलों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी विचार प्राप्त हुए। टीडीबी आत्मनिर्भर यात्रा पंजाब चैप्टर ने सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग की भावना को और मजबूत किया तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में पंजाब की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

निर्देश | **पंचकूला को साफ स्वच्छ व बेहतरीन शहर बनाने के लिए लिया संज्ञान**

विभागों को टोल फ्री नंबर जारी करने के दिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

जिला प्रशासन ने जिलावासियों की समस्याओं के मद्देनजर लिया संज्ञान

उपायुक्त सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने लोगों की समस्याओं व पंचकूला को साफ स्वच्छ व बेहतरीन शहर बनाने के लिए लिया संज्ञान।

एसडीएम ने बताया कि पंचकूला को स्वच्छ, साफ सुथरा और बेहतरीन शहर बनाने में जिला प्रशासन व सरकार की नई पहल। एसडीएम ने सभी विभागों को दिए निर्देश, अपने- अपने विभागों की समस्याओं को ठीक करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करें ताकि जिलावासी उस नंबर पर डायल कर अपनी समस्याओं को बताकर संबंधित विभाग से ठीक करवा सकें।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पीएमडीए, नगर निगम, एचएसआईआईडीसी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड को निर्देश दिए कि जिलावासियों की मूलभूत समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए ताकि लोगो को सरकार की सुविधाओं का समय पर लाभ मिल सके।

कटारिया ने जिला के नागरिकों से भी अपील की कि संबंधित विभाग को अपनी समस्याओं यानि की सडक, पार्क, पेयजल, सीवरेज खराब होने के बारे में ब्यौरा देकर उनका समाधान करवाएं। जिले की सडकों, पार्कों, पेयजल सुविधा, सीवरेज में अगर कोई परेशानी आती है तो उन समस्याओं के निवारण के लिए नीचे दिए गए विभागों में जाकर अपनी समस्या दर्ज करवाएं और उनका समय रहते निवारण करवाएं।एसडीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अपने अधिकार क्षेत्र के कार्यो का सूचि के बारे में भी लोगों को अवगत करवाएं ताकि जिलावासी बिना परेशानी के सरकार व जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ ले सकें।

जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों की बनाई लिस्ट, विवरण इस प्रकार है- सड़कों की समस्या को लेकर मुरम्मत हेतु- कटारिया ने बताया कि पंचकूला के सैक्टर-1,3,5 के अंदर की सडकें एचएसवीपी के डिविजन नंबर 1 के अंतर्गत आती हैं। सैक्टर-1,3,4 की टी प्वाईंट से साकेतडी की ओर जाने वाली, एचएसवीपी के शिवालिक कंट्री कल्ब के सामने साकेतडी से यूटी बाउंड्री नजदीक किशनगढ एचएसवीपी के डिविजन-2 के अधिकार क्षेत्र में आती है। एसडीएम कटारिया ने बताया कि इंटरनेल स्टोर्म लाईन सैक्टर-2,3,6, 5बी, 5सी और सैक्टर-7 के माता मनसा एमडीसी क्षेत्र की सडकें व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शिवालिक कंट्री कल्ब से साकेतडी की ओर जाने वाली व साकेतडी से किशनगढ जाने वाली सभी सडकें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के डिविजन-2 के अंतर्गत आती हैं।इन जगहों पर किसी भी प्रकार की संबंधित समस्या के लिए एचएसवीपी से संपर्क कर अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं। पंचकूला सैक्टर-7, 2,3 एमडीसी के डिवाईडिंग सडक जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है। एचएसवीपी डिविजन नंबर-2 के अंतर्गत आती है। सैक्टर-23,24,27,28,31 व 32 के सभी अंदर की सडकें एचएसवीपी डिविजन नंबर-2 के अंतर्गत आती है। पिंजौर क्षेत्र के सैक्टर-27/28, 27/30, 28/30 व सेक्टर-30 एचएसवीपी डिविजन नंबर-2 के अंतर्गत आती है। सभी पंचकूला के सैक्टर 1 से सैक्टर 21 पंचकूला एक्सटैंशन, सैक्टर-22 से सैक्टर-28 की सभी डिवाईडिंग सडकें पीएमडीए डिविजन नंबर-1 के अंतर्गत आती है। एमडीसी सैक्टर-1,2 साकेतडी गांव से यूटी बाउंड्री नजदीक महाशिव मंदिर से कैंबवाला गांव तक की सडकें पीएमडीए डिविजन नंबर-1 के अंतर्गत आती है। ओल्ड पंचकूला से पीर बाबा से यूटी बाउंड्री (कालका रोड) की सडकें पीएमडीए डिविजन नंबर-1 के अंतर्गत आती है। सैक्टर-4, 5 व एमडीसी के सैक्टर-5 ए की अंदर की सडकें नगर निगम कार्यकारी अभियंता पंचकूला के अंतर्गत आती है। एमडीसी सैक्टर-5डी के अंदर की सडकें माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड के अंतर्गत आती है।

'समाधान शिविर में आई समस्याओं का प्राथमिकता व तय समय सीमा में समाधान करने के दिए निर्देश'

आयुक्त एवं सचिव जन स्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ की समीक्षा

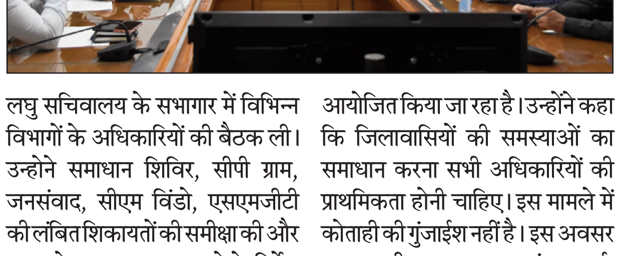

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

आयुक्त एवं सचिव जन स्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग मोहम्मद शाईन ने चंडीगढ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ समाधान शिविर में आई समस्याओं पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की।उन्होंने सभी उपायुक्तों को गंभीरता से व बिना विलंब के समाधान शिविर की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने आयुक्त एवं सचिव को आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है व शेष बची समस्याओं का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने इसके उपरांत लघु सचिवालय के सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने समाधान शिविर, सीपी ग्राम, जनसंवाद, सीएम विंडो, एसएमजीटी की लंबित शिकायतों की समीक्षा की और जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।उन्होने कहा कि समाधान शिविर में आने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिलावासी अपनी समस्या के समाधान के लिए परेशान न हों। इस कार्य में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए समाधान शिविर हर जिले में आयोजित किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि जिलावासियों की समस्याओं का समाधान करना सभी अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में कोताही की गुंजाईश नहीं है। इस अवसर पर एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगराधीश जागृति, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, तहसीलदार कालका विवेक गोयल, सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन जसमेर बंजारा, सत्यवान भारद्वाज, पब्लिक हेल्थ के कार्यकारी अभियंता समीर शर्मा, डीपीओ सविता नेहरा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।